कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

वैशाख–ज्येष्ठ 2082, मई 2025

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

विज़न 2047: समृद्ध और महान भारत

24–26 अप्रैल 2025, पूसा, नई दिल्ली

सचित्र झलक

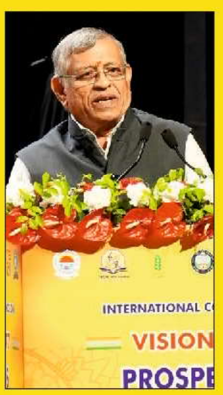

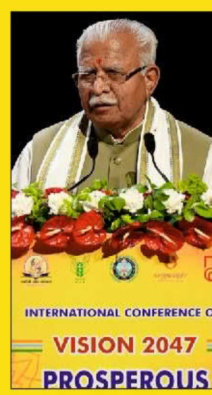

स्वदेशी पत्रिका

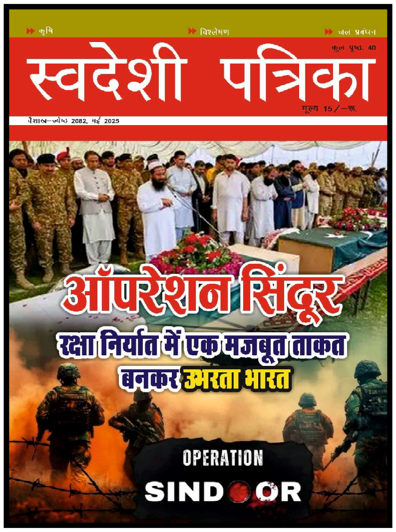

वर्ष–33, अंक–5
वैशाख–ज्येष्ठ 2082 मई 2025

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–06

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा निर्यात में एक मजबूत ताकत बनकर उभरता भारत

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 ऑपरेशन सिंदूर
पाकिस्तान को नहीं मालूम – एक चुटकी सिंदूर की कीमत
.... विंग कमांडर नंदलाल जोतवानी

10 ऑपरेशन सिंदूर
भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करता ऑपरेशन सिंदूर
.... विनोद जौहरी

13 आजकल
व्यापार युद्ध में टेरिफ का मसला: भारतीय हितों को आगे कर बात हो अमेरिका से
........अनिल तिवारी

15 मुद्दा
पानी और खून एक साथ कैसे बहेगा?
........डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

17 विश्लेषण
युद्धः विनाश का वैश्विक व्यापार और मानवता का सवाल
.... विवेकानंद माथने

19 बहस
अब पाकिस्तान के साथ बेटी व्यवहार बंद करें भारतीय मुसलमान
........डॉ बालाराम परमार 'हंसमुख'

21 ज्वलंत मुद्दा
सेना के साथ खड़ा भारत, सत्ता के लिए लड़ता पाकिस्तान
.... संजय सक्सेना

23 आर्थिकी
रुपए की बढ़ती ताकत एवं भारत में बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार
.... प्रहलाद सबनानी

25 बहस
ट्रम्प की अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति और भारत
........अनिल जवलेकर

27 पर्यावरण
संवेदनशीलता से प्रकृति के पुनर्जीवन की राह
........विजय गर्ग

29 गेमिंग
देश में ऑनलाइन लूडो के बढ़ते खतरे पर कैसे लगेगी लगाम
........अजय कुमार

31 पहल
भारतीय उत्पादों के लिए जरूरी है एक राष्ट्र–एक प्रतीक
........संगीता राव

पाठकनामा

आंतकवादियों को दिया करारा जवाब

22 अप्रैल 2025 को जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान–समर्थित आतंकी संगठन "द रेजिस्टेंस फ्रंट" (टीआरएफ) द्वारा एक भीषण आतंकी हमला किया गया, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई और इसका नाम रखा गया– ऑपरेशन सिंदूर।

'ऑपरेशन सिंदूर' भारत की आतंकवाद के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" नीति का स्पष्ट उदाहरण है। इस अभियान द्वारा न केवल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि पाकिस्तान को यह संदेश भी दिया कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

7 मई 2025 की रात्रि को भारतीय सशस्त्र बलों ने "ऑपरेशन सिंदूर" के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इन हमलों में जैश–ए–मोहम्मद और लश्कर–ए–तैयबा जैसे संगठनों के प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया गया। यहां तक कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार स्थित कई आतंकवादी ढांचों को नष्ट किया, जिससे पाकिस्तानी सेना में अफरातफरी मच गई।

कुल मिलाकर कह सकते है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया एक सटीक और निर्णायक सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब देना था। सेना के जाबांज अफसरों ने सफल अभियान से दुनिया भर में भारत को गौरव दिलाया है।

वरूण दीक्षित, बागपत, उ.प्र.

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता का प्रमाण है। इस दौरान हमारे सशस्त्र बलों थल सेना, नौसेना और वायु सेना का समन्वय अद्भुत था।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पौष्टिक उत्पादन बढ़ाने तथा दुनिया को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारत को विश्व की खाद्य टोकरी बनाने की आवश्यकता है।

शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री, भारत

भारत अब अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों के साथ बराबर के भागीदार के रूप में सहयोग कर रहा है। यह हमारी वैज्ञानिक क्षमता, दूरदर्शी नेतृत्व और शांतिपूर्ण अंतरिक्ष सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

जितेन्द्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री

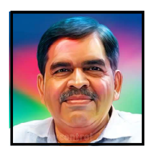

भारत अब अधिक रक्षा सामान निर्यात करने की बेहतर स्थिति में है। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की सैन्य साख को बढ़ाया है, बल्कि स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का जीवंत प्रदर्शन भी किया है।

डॉ. अश्वनी महाजन, अ.भा. सह–संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

अमेरिका से बाहर भेजे जाने वाली राशि पर करः एक प्रतिगामी कदम

हाल ही में, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीन कार्ड धारकों सहित विदेशी नागरिकों द्वारा भेजे जाने वाले धन पर 5 प्रतिशत लगाने की घोषणा कर दी। हालाँकि बाद में इसे संशोधित कर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया, लेकिन इस योजना ने व्यापक चिंता पैदा कर दी है, खासकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के बीच, जो विदेशी राष्ट्रीय कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, भारत को वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 129 अरब डॉलर में से केवल अमेरिका से 32 अरब डॉलर का धन प्राप्त हुआ। आने वाले वर्ष में यदि धन प्रेषण का स्तर समान भी रहे तो भी, प्रस्तावित कर के परिणामस्वरूप प्रभावी रूप से भारतीय परिवारों और भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलने वाली राशि में एक अरब डॉलर से ज़्यादा की कमी आ जाएगी।

ट्रम्प प्रशासन का उद्देश्य घोषित रूप से अमेरिकी सरकार के लिए अधिक राजस्व एकत्र करना और विदेशी देशों में धन को बाहर जाने से रोकना है। हालाँकि, यह दृष्टिकोण अदूरदर्शी और संभावित रूप से हानिकारक है। सर्वप्रथम प्रवासियों द्वारा धन प्रेषण, व्यावसायिक लाभ हस्तांतरण नहीं हैं; बल्कि वे व्यक्तिगत हस्तांतरण हैं। इन निधियों पर संघीय और राज्य आयकरों के माध्यम से पहले ही संयुक्त राज्य अमरीका में कर लगाया जा चुका हो तो, इन हस्तांतरणों पर कराधान की दूसरी परत लगाना अन्यायपूर्ण और आर्थिक रूप से प्रतिगामी दोनों है। इसके अलावा, ऐसा कर अभूतपूर्व है। वैश्विक स्तर पर, वस्तुतः ऐसे कोई उदाहरण नहीं हैं जहाँ सरकारें वैध विदेशी श्रमिकों द्वारा विदेश भेजे गए धन पर कर लगाती हों। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी के देश, कहीं पर भी ऐसे कर नहीं लगाये जाते। यह सही है कि यह कदम संयुक्त राज्य अमरीका से भारत में धन प्रेषण को हतोत्साहित कर सकता है, जो न केवल इन निधियों पर निर्भर लाखों भारतीय परिवारों को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर धन प्रेषण पर कर कुशल अप्रवासियों – विशेष रूप से भारत से आने वाले लोगों – को नकारात्मक संदेश भी भेजेगा, जो संयुक्त राज्य अमरीका की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अमेरिका में सबसे सफल और उत्पादक अप्रवासी समुदायों में से एक भारतीयों का है। इंडियास्पोरा और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मूल के लोग, अमेरिकी आबादी का केवल 1.5 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद, कुल आयकर में 5 से 6 प्रतिशत योगदान करते हैं – अनुमानित 250–300 अरब डालर सालाना। यह न केवल भारतीयों की उच्च आय को दर्शाता है, बल्कि एक मजबूत कार्य नैतिकता, शैक्षिक उत्कृष्टता और उद्यमशीलता की भावना का भी प्रतिबिंब है। कोई भी आसानी से समझ सकता है कि अमेरिकी सरकार द्वारा गरीब अमेरिकी परिवारों को दी जा रही मदद, आंशिक रूप से भारतीय मूल के लोगों से अर्जित अतिरिक्त राजस्व से वित्तपोषित है।

अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से अप्रवासियों, विशेष रूप से भारत जैसे देशों से कुशल पेशेवरों से लाभ उठाया है। सिलिकॉन वैली में तकनीकी उछाल का मुख्य कारण अप्रवासी नवाचार था। गूगल, माइक्रोसॉट और एडोब जैसी कंपनियों का नेतृत्व भारतीय मूल के सीईओ– क्रमशः सुंदर पिचाई, सत्य नडेला और शांतनु नारायण ने किया है। उनके नेतृत्व ने न केवल उनकी कंपनियों को बदल दिया है, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, विदेशी नागरिक अक्सर विशेष कौशल और ज्ञान लेकर आते हैं जो घरेलू कार्यबल के पूरक होते हैं। भारतीय पेशेवर, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण कौशल की कमी की भरपाई करते हैं और वैश्विक बाजारों में अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने में मदद करते हैं। जबकि भारत में काम करने वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या अमरीका में काम करने वाले भारतीयों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, इस सिद्धांत को अन्य वित्तीय प्रवाहों पर लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत अमरीकी कंपनियों द्वारा बाहरी प्रेषण पर कर लगाने का विकल्प चुन सकता है। भारत में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियाँ अक्सर रॉयल्टी, लाइसेंस फीस या तकनीकी सेवाओं के भुगतान के रूप में बड़ी मात्रा में धन वापस अमेरिका भेजती हैं। इन पर अधिक सख्ती से कर लगाया जा सकता है, जिससे अक्सर कर से बचने के लिए इन कंपनियों द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों से भी निपटा जा सकता है।

सरकार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) पर भी कर लगा सकती है। अमेरिका में स्थित बड़ी संख्या में एफआईआई भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करते हैं। हालांकि वे बाजार में तरलता में योगदान जरूर करते हैं, उनकी सट्टा गतिविधियों से महत्वपूर्ण अस्थिरता भी पैदा होती है। भारत उनके प्रत्यावर्तित मुनाफे पर एक छोटा कर लगा सकता है – प्रभावी रूप से टोबिन टैक्स का एक संस्करण, जिसका नाम अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन के नाम पर रखा गया है। टोबिन ने अल्पकालिक पूंजी प्रवाह को हतोत्साहित करने के लिए मुद्रा रूपांतरण पर कर लगाने का सुझाव दिया था। टोबिन टैक्स, राजस्व में वृद्धि और सट्टा डॉलर के बहिर्वाह को हतोत्साहित करने जैसे दो उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। हर बार जब रुपये को यू.एस. में भेजने के लिए डॉलर में परिवर्तित किया जाता है, तो एक छोटा लेनदेन कर लगाया जा सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति को समझना पड़ेगा कि एक वैश्वीकृत दुनिया में, सहयोग और आपसी सम्मान, संरक्षणवाद और राजकोषीय अतिक्रमण की तुलना में बेहतर परिणाम देते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रशासन को तत्काल लाभ से इतर, दीर्घकालिक निहितार्थों के मद्देनजर, इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहिए।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा निर्यात में एक मजबूत ताकत बनकर उभरता भारत

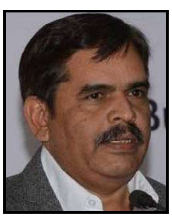

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और युद्धक्षेत्र में सिद्ध प्रदर्शन के साथ, भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बनने के लिए तैयार है, जो शुद्ध आयातक से वैश्विक सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में शुद्ध और बड़ा योगदानकर्ता बन रहा है..

– डॉ. अश्वनी महाजन

पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ भारत द्वारा छेड़े गए युद्ध के केवल चार दिनों के बाद हुए युद्ध विराम ने इस आतंकवादी राष्ट्र को और अधिक नुकसान से बचा लिया है, लेकिन इस छोटी सी अवधि में पाकिस्तान को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और दूसरी तरफ अगर हम संघर्ष के इन चार दिनों को देखें, तो भारत निश्चित रूप से अपनी रक्षा क्षमताओं, विशेष रूप से स्वदेशी रक्षा उपकरणों को वैश्विक स्तर पर अपने संबंधित श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ के बराबर या उससे भी बेहतर प्रदर्शित करने में सक्षम रहा है।

भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, "ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय प्रणालियों द्वारा शत्रु की प्रौद्योगिकियों को बेअसर करने के ठोस सबूत भी पेश किए – चीनी पीएल–15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, तुर्की मूल के यूएवी, लंबी दूरी के रॉकेट, क्वाडकॉप्टर और वाणिज्यिक ड्रोन के टुकड़े बरामद किए गए।" पीआईबी आगे कहता है, "जिन्हें बरामद किया गया और उनकी पहचान की गई, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान द्वारा विदेशों से आपूर्ति किए गए उन्नत हथियारों का फायदा उठाने के प्रयासों के बावजूद, भारत का स्वदेशी वायु रक्षा तंत्र और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध नेटवर्क बेहतर बना हुआ है।"

गौरतलब है कि भारत का रक्षा निर्यात 2013–14 में 686 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023–24 में 21,083 करोड़ रुपये हो गया; और 2024–25 में यह 23,622 करोड़ रुपये हो गया। अगले वर्ष के लिए भारत का लक्ष्य 35000 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरण निर्यात करना है। भारत अब इटली, मालदीव, रूस, श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजरायल, स्पेन और चिली सहित 85 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है।

भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रमुख रक्षा उपकरणों में शामिल हैं– 'आकाश' सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जिसे आर्मेनिया जैसे देशों को निर्यात किया गया है और सूडान में प्रदर्शित किया गया। 'ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल', जिसे फिलीपींस को निर्यात किया जा रहा है और अन्य दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों ने भी इसमें रुचि दिखाई है (सौदों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं); पिनाका मल्टी–बैरल रॉकेट लांचर, जिसे आर्मेनिया को निर्यात किया गया, 155 मिमी आर्टिलरी गन, जिसे आर्मेनिया को निर्यात किया गया, जो उन्नत आर्टिलरी प्रणालियों में भारत की क्षमताओं को उजागर करता है; डोर्नियर–228 विमान, जिसे परिवहन और निगरानी भूमिकाओं के लिए विभिन्न देशों को निर्यात किया गया।

हालांकि, इन रक्षा वस्तुओं की विभिन्न देशों में पहले से ही मांग है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद, परिदृश्य भारत के रक्षा निर्यात के पक्ष में और भी बदल गया है। भारत अब अधिक रक्षा सामान बेचने की बेहतर स्थिति में है। इस ऑपरेशन ने न केवल भारत की सैन्य साख को बढ़ाया है, बल्कि स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा प्रणालियों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का जीवंत प्रदर्शन भी किया है।

कैसा रहा प्रदर्शन?

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 'मेड इन इंडिया' हथियारों की प्रामाणिकता साबित हुई है। आज दुनिया देख रही है कि 21वीं सदी के युद्ध में

मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों का समय आ गया है। भारत ने अपनी क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया है और नए युग के युद्ध में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। इसने भारत को स्वदेशी हथियारों और रक्षा प्रणालियों को कार्रवाई में प्रदर्शित करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान किया है। वास्तव में, हम युद्ध के मैदान में भारत के वर्तमान कार्य को दुनिया में भारत निर्मित हथियारों के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने वाला एक प्रचार अभ्यास कह सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वे परीक्षण केवल मैदान में नहीं बल्कि चीन और तुर्की जैसी प्रमुख सैन्य शक्तियों द्वारा समर्थित वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति में सिद्ध हुए हैं।

आकाश मिसाइल सिस्टम

इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि भारत–पाकिस्तान तनाव के बीच, आकाश मिसाइल ने अपनी 'अग्नि परीक्षा' पास कर ली है। उल्लेखनीय है कि आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत की स्वदेशी प्रणाली है, जिसने हाल ही में भारत–पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अपनी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। इस प्रणाली को भारत द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के साथ 15 वर्षों में विकसित किया गया है। आकाश ने दुश्मन देश की ओर से आने वाले ड्रोन और मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक दिया और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए युद्ध क्षेत्र में अपनी ताकत साबित की। उल्लेखनीय है कि आर्मेनिया पहला देश है जिसने 6000 करोड़ रुपये की लागत से 15 आकाश मिसाइल प्रणाली का ऑर्डर दिया था और पहली खेप पिछले साल ही भेजी जा चुकी है। लेकिन संघर्ष के दौरान आकाश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से सबका ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रणाली को डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के कुशल मार्गदर्शन में विकसित किया गया था, जो भारत के 'मिसाइल मैन' के रूप में लोकप्रिय हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत केवल 500 करोड़ रुपये के मामूली निवेश के साथ इस बेहद प्रभावी मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित करने में सक्षम रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आकाश किसी भी दिशा से वास्तविक समय में कई लक्ष्यों को ट्रैक और भेद सकता है। यह 70 किलोमीटर दूर से एक मिसाइल का पता लगा सकता है और इसे 30 किलोमीटर पर नष्ट कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आकाश और एस–400 ट्रायम्फ सहित भारत की रक्षा प्रणाली अभेद्य दीवार की तरह खड़ी रही। अब जब आकाश मिसाइल प्रणाली की सफलता संदेह से परे साबित हो चुकी है, इस स्थिति में भारत दुनिया भर से भारी मात्रा में ऑर्डर की उम्मीद कर सकता है। अगर हमें सिर्फ 200 मिसाइलों के लिए भी ऑर्डर मिलते हैं तो इससे 30000 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है।

ब्रह्मोस

भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत–पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पहली बार युद्ध के मैदान में दिखी, जब इसे 10 मई, 2025 को उपयोग में लाया गया। बताया जाता है कि भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान द्वारा भारत के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के प्रयास के जवाब में पाकिस्तान के अंदर कई रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया। हालांकि, भारत सरकार या भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन संघर्ष अवधि के दौरान ही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह पता चला है कि 12 जून 2001 को इसके सफल परीक्षण के बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है और यह दो चरणों वाली मिसाइल है। पहले चरण में यह ध्वनि की गति से भी अधिक गति से चलती है और फिर मारक हिस्सा अलग होकर दूसरे चरण में यह ध्वनि की गति से तीन गुना अधिक गति से लक्ष्य पर पहुँचता है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर बहुत ही सटीक निशाना लगाया है और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के सहयोग से भारत ने विकसित किया है, इसलिए पश्चिमी देशों में इसके विपणन में कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से, ब्रह्मोस की सिद्ध सफलता के कारण इसके बाजार में वृद्धि हो सकती है।

एसआईपीआरआई के अनुसार, वर्ष 2020 और 2024 के बीच रक्षा वस्तुओं का वैश्विक निर्यात सालाना 138 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। शीर्ष पांच हथियार निर्यातक देश अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी हैं, जिनकी हिस्सेदारी क्रमशः 43 प्रतिशत, 9.6 प्रतिशत, 7.8 प्रतिशत, 5.9 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत है। सामूहिक रूप से, इन पांच देशों के पास इस अवधि के दौरान दुनिया के हथियारों के निर्यात का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा था। समझना होगा की वैश्विक रक्षा निर्यात पर अब केवल कुछ खिलाड़ियों का दबदबा नहीं रह गया है। हालांकि अमेरिका, रूस और फ्रांस अभी भी अग्रणी हैं, लेकिन भारत, दक्षिण कोरिया, तुर्की और इज़राइल जैसे देश तेजी से बाज़ार हासिल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और युद्धक्षेत्र में सिद्ध प्रदर्शन के साथ, भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बनने के लिए तैयार है, जो शुद्ध आयातक से वैश्विक सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में शुद्ध योगदानकर्ता बन रहा है। इसके साथ ही भारत की रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के सभी लक्ष्यों को भेदने के प्रयासों को विफल कर दिया, और भारत के स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों की श्रेष्ठता को संदेह से परे साबित कर दिया।❑❑

पाकिस्तान को नहीं मालूम एक चुटकी सिंदूर की कीमत

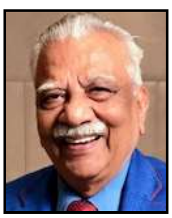

'ऑपरेशन सिंदूर' उन लोगों को भारत की ओर से करारा जवाब है, जो हमारी सीमाओं, सेना और नागरिकों को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं, यह कार्रवाई पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की "ज़ीरो टॉलरेंस" की नीति का प्रमाण है।

– विंग कमांडर नंदलाल जोतवानी

22 अप्रैल 2025 को लश्कर–ए–तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बर हमला किया. इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण बंदूक की गोलियों से, उनके परिवारों के सामने, सिर पर गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया गया. इस हमले का उद्देश्य जम्मू–कश्मीर में अस्थिरता लाना, पर्यटन को क्षति पहुंचाना और वहाँ की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बिगाड़ना था, मगर भारत ने सूझ–बूझ और पराक्रम से पाक के नापाक इरादे विफल कर दिए।

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारतीय पर्यटकों के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए 7 मई 2025 को प्रातः 1:03 बजे और 1:30 बजे के बीच 'ऑपरेशन सिन्दूर' को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया और पाकिस्तान व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पाकिस्तान ऑक्यूपाईड कश्मीर–पीओके) पर 28 मिनट की 'एयर स्ट्राइक' में नौ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया।

समाचार एजेंसी 'रॉयटर्स' के मुताबिक, इस 'एयर स्ट्राइक' में पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या 31 है और 46 लोग घायल हैं। उक्त समाचार एजेंसी ने यह जानकारी पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के हवाले से दी है मगर वास्तव में हताहत हुए लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इस 'एयर स्ट्राइक' में आतंकी मसूद अजहर ने अपने परिवारवालों को भी खोया और कहा कि उसकी पत्नी, उस के भांजे व भांजी समेत परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है। उसने कहा कि वह भी इन मृत लोगों के काफिले में शामिल होता मगर अल्लाह से मुलाकात का वक्त पक्का है और वह आगे–पीछे नहीं हो सकता।

ये हमले नौ चिन्हित स्थानों – मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, रावलकोट, चकस्वरी, भीमबर, नीलम घाटी, झेलम, चकवाल– में किए गए. ये कार्रवाई नपी–तुली और गैर–उत्तेजित प्रकृति की, आनुपातिक और जिम्मेदाराना थी, जो पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद और भारत पर हमलों के निरंतर समर्थन के विरोध में तथा आगामी आशंकित आक्रमण रोकने के लिए अंजाम दी गई।

शीर्ष अदालत के न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, देश के नागरिक के रूप में हमें अपने सैन्य बलों पर गर्व करना चाहिए, जिन्होंने देश विरोधी गतिविधियों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा, भारतीय सशस्त्र बल हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करते हैं। कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और खतरे का सामना करने की तत्परता ऐसी चीज है जिसे हर नागरिक को पहचानना और सम्मान देना चाहिए।

करे ताकि आतंकवाद को विश्व–पटल से आमूल नष्ट किया जाए।

इस 'एयर स्ट्राइक'को सिर्फ आतंकी ट्रेनिंग शिविरों और उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर तक सीमित रखा गया। सशस्त्र सेनाओं ने सटीकता, सतर्कता और मानवीयता का परिचय दिया है, जिसके लिए पूरी सशस्त्र सेना और प्रधानमंत्री हार्दिक साधुवाद के पात्र हैं।

उधर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी जनता को झूठा ढाढ़स बँधा रहे है कि पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया है और पाकिस्तानी वायु सेना ने भारत के पाँच विमान मार गिराए हैं, जिनमें तीन 'राफेल' भी शामिल हैं। पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर भी ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसमें वह खुद को विजयी बता रहा है, मगर हक़ीक़त यह है कि भारत के निशाने पर 12 आतंकी ठिकाने हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी जनता को झूठा ढाढ़स बँधा रहे है कि पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया है और पाकिस्तानी वायु सेना ने भारत के पांच विमान मार गिराए हैं, जिनमें तीन 'राफेल' भी शामिल हैं। पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर भी ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसमें वह खुद को विजयी बता रहा है, मगर हक़ीक़त यह है कि भारत के निशाने पर १२ आतंकी ठिकाने हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' उन लोगों को भारत की ओर से करारा जवाब है, जो हमारी सीमाओं, सेना और नागरिकों को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं, यह कार्रवाई पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की "ज़ीरो टॉलरेंस" की नीति का प्रमाण है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर कहा कि 'अपनी धरती पर हमले का जवाब देने के लिए, भारत ने अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल किया है।'

पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा कि "ऑपरेशन सिंदूर" ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों को एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, हम सभी उपमहाद्वीप में मौजूदा घटनाक्रमों को लेकर बहुत चिंतित हैं। देश के नागरिक होने के नाते, हमें पूरे दिल से सरकार का समर्थन करना चाहिए और उसके साथ खड़ा होना चाहिए।

भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' द्वारा यह भी संदेश भी दिया है कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत के इस सतत संग्राम में सारा विश्व सम्मिलित होकर सहयोग

कुल मिलाकर "पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त"! ❑❑

(लेखक भारत सरकार के पूर्व राष्ट्रीय कमीशनर हैं।)

भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करता ऑपरेशन सिंदूर

पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बायसरन घाटी में 26 निर्दोष हिन्दू पर्यटकों के धर्म पूछ कर उनकी हत्या कर दी। इस हमले का जवाब देने के लिए भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया। ये उन महिलाओं का प्रतीक है, जिन्होंने आतंकी हमले में अपने पतियों को खोया है। जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत द्वारा 7 मई 2025 से 10 मई 2025 तक चले ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सैन्य सुरक्षा को नष्ट भ्रष्ट करके उसको घुटनों पर लाकर और अमेरिका, चीन और तुर्की के कहने पर सीजफ़ायर के लिए गिड़गिड़ाने के लिए भारत से निवेदन करने के लिए बाध्य कर दिया। यह घटनाक्रम बहुत जटिल है किंतु मात्र चार दिन में भारत ने अमेरिका, चीन के साथ–साथ दिन प्रतिदिन अपने परमाणु बमों और आतंकवाद के बूते पर भारत को धमकाने वाले पाकिस्तान को भारत की ताकत का आभास करा दिया है। ऑपरेशन को लेकर सेना की दो महिला सैन्य अफसरों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ही देश को सैन्य कार्रवाई के बारे में बताया।

पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति को लेकर बड़े–बड़े दावे करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। भारत सैन्य बल, हथियारों और रक्षा तकनीक पर खर्च के मामले में दुनिया की सर्वोच्च 5 सैन्य शक्तियों में सम्मिलित है, जबकि पाकिस्तान इस सूची में काफी पीछे है। यही कारण है कि सैन्य ताकत के मोर्चे पर भारत को चुनौती देना पाकिस्तान के लिए केवल एक खोखला दावा भर है। स्वीडन स्थित प्रमुख थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान की तुलना में करीब 9 गुना अधिक रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बीच वैश्विक परिपेक्ष्य में भारत की ताकत बढ़ी है और उसके हथियारों की मांग बढ़ रही हैं। 17 देशों ने हाल में भारत में निर्मित हथियारों के प्रति अपनी रुचि दिखाई है।

भारत द्वारा 7 मई 2025 से 10 मई 2025 तक चले ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सैन्य सुरक्षा को नष्ट भ्रष्ट करके उसको घुटनों पर लाकर और अमेरिका, चीन और तुर्की के कहने पर सीजफ़ायर के लिए गिड़गिड़ाने के लिए भारत से निवेदन करने के लिए बाध्य कर दिया।

– विनोद जौहरी

चीन ने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया है और अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच पाक अधिकृत जम्मू काश्मीर के विषय में मध्यस्तता का प्रस्ताव किया है।

भारत की उभरती महाशक्ति से विचलित अमेरिका जो कल तक टैरिफ नीति से चीन की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का प्रयास कर रहा था वह भी चीन के साथ अपनी टैरिफ नीति को विराम देकर अपने सम्बन्धों को पुनर्जीवित कर रहा है।

चीन इसलिए भी चिंतित है कि उसने भी भारत का कश्मीर और लद्दाख का बड़ा भूभाग पाँच दशकों से अपने अवैध कब्जे में लिया हुआ हैं और भारत द्वारा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर वापस अपने अधिकार में लेने से उसका 65 बिल्यन डॉलर का निवेश और उसकी पाकिस्तान से सीधा संपर्क समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान के समर्थक और हथियारों की आपूर्ति करने वाले देश तुरकिए और अज़रबैजान के विरुद्ध भी भारत में बहुत आक्रोश है।

यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का चरित्र बादल जाएगा, सही नहीं है। जैसी सूचनाएँ पाकिस्तान टीवी चैनलों, मीडिया रेपोर्ट्स से आ रही हैं, उनके अनुसार पाकिस्तान कि सरकार और सेना आज भी आतंकवादियों के साथ खड़ी हैं और मसूद अजहर जैसे जैश आतंकी सरगनाओं को करोड़ों रुपये का मुआवजा दे रही है और जो आतंकी बेस कैंप और ठिकाने भारत के हमले में नष्ट हो गए थे उनका इनफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा किया जा रहा है। भारत के आक्रमण में मृत आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी सम्मिलित हुए।

दूसरी तरफ सिंधु नदी समझौते के निरस्त होने से पाकिस्तान में त्राहि त्राहि मची है और उनकी सरकार आग बबूला है।

भारत के इतिहास में स्वतन्त्रता के बाद 78 वर्षों में पाकिस्तान और चीन द्वारा थोपे गए पाँच युद्ध लड़े जा चुके हैं और पिछले चालीस वर्षों में पाकिस्तान ने भारत को बहुत गहरे घाव दिये हैं। केवल वर्ष 2001 से ही भारत 48 बड़े आतंकवादी हमले पूरे देश में झेल चुका है। प्रत्येक युद्ध अपने जख्म छोडता है और देश को और अधिक सुदृढ़ करने का अवसर देता है। इज़राएल का उदाहरण सामने हैं जो हर तरफ से शत्रुओं से घिरा है और अकेला सब पर भारी है जबकि इज़राएल में तीस प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम अरबों की है और आंतरिक राजनीतिक विरोध वहाँ भी होता है।

ऑपरेशन सिंदूर के तथ्य सभी टीवी चैनलों, समाचार पत्रों और मीडिया में आ रहे हैं फिर भी यह इतने महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व हैं कि इनको सहेजना आवश्यक हो जाता है। कालांतर में इस पर पुस्तकें भी लिखी जाएंगी और पिछले युद्धों पर विशेषकर सेना के वरिष्ठ पूर्व अधिकारियों ने सम्पूर्ण तथ्यों के साथ पुस्तकें लिखी हैं।

इस हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल संधि के निलंबन से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने तक कई पाबंदियां लगाईं। यहां तक की वैश्विक स्तर पर भी इस हमले की निंदा की गई।

भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश–ए–मोहम्मद, लश्कर–ए–तैयबा और हिज्बुल मुजाहिदीन के मुख्यालयों को निशाना बनाकर रात के समय नौ ठिकानों पर विशेष कार्रवाई की गई। ऑपरेशन में निशाना बनाए गए 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान के अंदर और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे। पाकिस्तान के जिन शहरों में हमले हुए उनमें बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट प्रमुख हैं। हमलों के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन और अन्य सटीक हथियार प्रणालियों का उपयोग किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख देशों को भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। भारत की तीनों सेनाओं (थल, वायु और नौसेना) ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने बात की।

एलओसी के पास स्थित जिन 5 टारगेट्स पर अटैक किया गया, उनमें सवाईनाला कैंप, मुजफ्फराबाद जो पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह लश्कर–ए–तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था।

सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह जैश–ए–मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटर और जरनल सर्वाइविंग ट्रेनिंग का केंद्र भी था।

गुलपुर कैंप, कोटली: यह एलओसी 30 किलोमीटर दूर था. लश्कर–ए–तैयबा का बेस था, जो रजौरी और पुंछ में सक्रिय था।

बरमाला कैंप, बिंबर: यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आइडी और जंगल सर्वाइवल केंद्र का प्रशिक्षण दिया जाता था।

अब्बास कैंप, कोटली: यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर–ए–तैयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 आतंकियों को ट्रेन करने की थी।

इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर जिन टारगेट्स (नार्मल प्लांट) पर अटैक

किया गया उनमें –

1. सर्जल कैंप, सियालकोटः यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है. मार्च 2025 जम्मू–कश्मीर के चार जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था।

2. महमूना जाया कैंप, सियालकोटः यह 12 से 18 किलोमीटर आईबी से दूर था, हिजबुल–मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ में आतंक फैलाने का केंद्र था. पठानकोट एयरबेस हमला भी यहीं से प्लान किया गया था।

3. मरकज तैयबा मुरीदकेः यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है. 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से परिशिक्षित हुए थे। अजमल कसाब और डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे।

4. मरकज सुभानअल्लाह, भवलपुरः यह इंटरनेशनल सीमा से 100 किलोमीटर दूर है, यह जैश–ए–मोहम्मद का केंद्र था।

ऑपरेशन सिंदूर में 7 मई को मारे गए 100 से अधिक दुर्दांत आतंकियों की जो सूचना मिली है, उनमें पाँच सरगना सम्मिलित हैं।

1. मुदस्सर खडियान उर्फ अबू जुंदालः लश्कर–ए–तैयबा का आतंकवादी। मुरीदके में मरकज तैयबा का प्रभारी था। यह 26 नवंबर 2008 मुंबई में हुए आतंकी हमले में शामिल था। पाकिस्तानी सेना ने अंतिम संस्कार में इसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

2. हाफिज मुहम्मद जमीलः जैश–ए–मोहम्मद का बड़ा आतंकवादी। मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला। बहावलपुर में मरकज सुब्हान अल्लाह का प्रभारी। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और फंडिंग में सक्रिय था।

3. मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी, मोहम्मद सलीम, घोसी साहबः जैश–ए–मोहम्मद का आतंकी और मसूद अजहर का साला। आतंकी संगठन में हथियारों के प्रशिक्षण का प्रभारी। जम्मू–कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था और आईसी–814 विमान अपहरण यानी कंधार हाईजैक की साजिश रचने वालों में सम्मिलित था।

4. खालिद उर्फ अबू अकाशाः लश्कर–ए–तैयबा का आतंकी। अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में सम्मिलित था। जम्मू–कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल। फैसलाबाद में अंतिम संस्कार हुआ। इसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी सम्मिलित हुए।

5. मोहम्मद हसन खानः जैश–ए–मोहम्मद का आतंकी। पिता पीओके में जैश–ए–मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी। मो. हसन की जम्मू–कश्मीर में आतंकी हमलों की योजना में अहम भूमिका थी।

पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने शुक्रवार 8 मई 2025 को रात 7.47 से रात 10. 57 के बीच पाकिस्तान ने जम्मू–कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 शहरों में 550 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। इस हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया।

7 से 9 मई के दौरान पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में भारत ने लाहौर समेत पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। एलओसी पर भी जवाबी कार्रवाई में भारत ने पुंछ–राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा नागरिक इलाकों पर की गई गोलाबारी का सटीक जवाब देते हुए आतंकियों के बंकर और सेना की चौकियों को नष्ट कर दिया। रहीमयार खान एयरबेस के मलबे में मिली आसिफ अली ज़रदारी की अधजली तस्वीर पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य विफलता का प्रतीक बन गई। साथ ही, भारत ने 9–10 मई की रात को पाकिस्तान के 11 एयरफोर्स बेस पर जवाबी कार्रवाई की, जिनमें नूर खान, रफीकी, मुरिद, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चुनीयन, सरगोधा, स्कारु, भोलारी और जैकोबाबाद शामिल हैं। जैकोबाबाद के शाहबाज एयरबेस की पहले और बाद की तस्वीरों ने तबाही की भयावहता को स्पष्ट किया। इन हमलों में एफ–16 और जेएफ–17 लड़ाकू विमानों वाले बेसों को नुकसान पहुंचा, जिससे पाकिस्तानी वायुसेना की 20 प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गई। वहीं, भोलारी एयरबेस पर हुए हमले में पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 50 से अधिक सैन्यकर्मियों की मौत हो गई और कई लड़ाकू विमान नष्ट हो गए। एयर मार्शल ए.के. भारती ने वीडियो दिखाते हुए बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान एयर डिफेंस रडार और एयरफील्ड का नुकसान हुआ है। उन्होंने पासरूर एयर डिफेंस रडार चुनियां एयर डिफेंस रडार, अरीफवाला एयर डिफेंस रडार, सरगोधा एयरफील्ड, रहीम यार खान एयरफील्ड, चकलाला एयरफील्ड (नूर खान), सुक्कुर एयरफील्डट, भुलारी एयरफील्ड, जैकोबाबाद एयरफील्ड में हुई स्ट्राइक और उसके असर के वीडियो भी साझा किए। भारत के आक्रमण में पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार उनके 50 सैनिक और ऑफिसर मारे गए।

ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय सेना सक्षम है। ❏❏

व्यापार युद्ध में टेरिफ का मसला

भारतीय हितों को आगे कर बात हो अमेरिका से

दुनिया भर में एक मशहूर कहावत है कि पैसा सिर चढ़कर बोलता है। अमेरिका फर्स्ट के अपने चुनावी वादे को आगे कर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अधिक से अधिक पैसा बटोरने के चक्कर में न सिर्फ मनमाने ढंग से टैरिफ लगाए जाने की घोषणा कर रहे हैं बल्कि इसके लिए अलग–अलग तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं।

अभी हाल ही में दिए अपने एक बयान में ट्रंप ने दावा किया कि 'भारत ने ट्रेड में जीरो टैरिफ डील का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा, भारत ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने की पेशकश की है, जिसमें मूल रूप से यह प्रस्ताव है कि अमेरिकी वस्तुओं की एक रेंज पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में व्यापार अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान ट्रंप ने यह दावा किया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयंशकर ने ट्रंप के दावे को नकारते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, ट्रेड पर अमेरिका से बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी तय नहीं है। ट्रंप के बयान पर जयशंकर ने कहा, ये जटिल वार्ताएं हैं। जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई भी व्यापार सौदा परस्पर लाभकारी होना चाहिए। इसे दोनों देशों के लिए कारगर होना चाहिए। व्यापार सौदे से हमारी यही अपेक्षा होगी। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, इस पर कोई भी निर्णय लेना जल्दबाजी होगी।

देश को आत्मनिर्भर बनाने की गरज से स्वावलंबी अभियान चला रहे स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि भारत उत्पादन के मोर्चे पर सक्षम है। भारत को व्यापार के मोर्चे पर अमेरिका सहित दुनिया के देशों के साथ खड़ा होना चाहिए, तथा भारतीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए सहमति समझौते करने चाहिए।

–अनिल तिवारी

मालूम हो कि ट्रंप सत्ता में आने के बाद से ही अमेरिकी खजाने को समृद्ध करने के नाम पर विभिन्न देशों के साथ व्यापार युद्ध का मोर्चा खोले हुए हैं। सामने के देश भी अपनी दक्षता और क्षमता के हिसाब से जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिकी टेरिफ के जवाब में जब चीन ने पलटवार किया तो ट्रंप ने अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि हो सकता है अमेरिकी बच्चों को 30 की बजाय दो गुड़िया ही मिले और इन दो गुड़ियों की कीमत 30 गुड़ियों से ज्यादा चुकानी पड़े तो भी अमेरिका को ही फायदा होगा। लेकिन आंकड़े गवाह है की ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद पहले 3 महीनों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 0.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। तब ट्रंप ने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को जिम्मेदार ठहराते हुए पूर्व राष्ट्रपति के 'ओवरहैंग' से छुटकारा पाने की बात कही थी।

लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर अमेरिका ने गत 9 अप्रैल 2025 को भारत समेत कई देशों पर लगाए गए भारी टैरिफ को 90 दिन के लिए टाल दिया था। दुनिया के सबसे बड़े खरीददार अमेरिका और सबसे बड़े दुकानदार चीन के बीच बनी इस सहमति में अमेरिका ने चीनी सामानों पर आयात शुल्क को 145 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत कर दिया है, इसी तरह चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ को 125 प्रतिशत से काम

करके 10 प्रतिशत किया है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद बाजार में उछाल आया लेकिन धीरे–धीरे उछाल का जोश ठंडा पड़ता जा रहा है। ऐसे में बाजार के जानकारों का कहना है कि इस समझौते को भविष्य में किस रूप में देखा जाएगा। क्या इस दिन से अमेरिका–चीन ट्रेड वॉर में नरमी की शुरुआत हुई या एक बार फिर दुनिया खामोशी से मुक्त व्यापार से हटकर 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ की तरफ बढ़ चली है? अभी औसत वैश्विक टैरिफ केवल 2.6 प्रतिशत है दरअसल इन सवालों के जवाब के लिए हमें यह समझना होगा कि व्यापार को बढ़ाने में टैरिफ की क्या भूमिका है।

वर्ष 1947 मेंविश्व व्यापार 60 मिलियन डॉलर का था जो वर्ष 2023 में 25 ट्रिलियन डॉलर का हो गया यानी 400 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ वैश्विक जीडीपी केवल 26 गुना ही बढी। जाहिर है देश द्वारा आयात शुल्क कम करने और अपने बाजार को खोल देने से व्यापार में तेजी आई। आज लगभग 75 प्रतिशत वैश्विक व्यापार टेरिफ मुक्त है। जो लोग अमेरिका के चीनी सामानों पर टेरिफ घटाने को लेकर खुश हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि कुछ साल पहले तक अमेरिका के ज्यादातर टैरिफ तीन प्रतिशत से भी कम हुआ करते थे।

अब सवाल है कि अमेरिका अपने दूसरे व्यापारिक साझेदारों पर कितना टैरिफ लगाता है? पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें पिछले चार महीनों के घटनाक्रम को याद करना होगा। इस साल जनवरी में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की शुरुआत चीन से की। जवाब में चीन ने भी पलटवार किया। इस ट्रेड वॉर का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

ट्रंप ने 2 अप्रैल को 57 देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। लेकिन, चीन और जापान ने अमेरिकी बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया, उधर अमेरिका में विरोध–प्रदर्शन शुरू हो गए। इसने ट्रंप को मजबूर किया कि– वह नए टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दें। इस तरह ट्रंप ने अन्य देशों को 8 जुलाई तक का समय दिया है कि अमेरिका के साथ जल्द से जल्द ट्रेड डील कर लें।

ब्रिटेन, जापान, कोरिया, वियतनाम और भारत सहित उन देशों पर दबाव हैं, जिन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। अमेरिका का पहला समझौता ब्रिटेन के साथ हुआ, फिर चीन के साथ। अब ट्रंप की नजरें भारत पर हैं। नई दिल्ली पर एक मिनी डील साइन करने का दबाव हो सकता है। इसमें पूरे ट्रेड एग्रीमेंट के बजाय टैरिफ में कटौती और बड़ी खरीदारी पर जोर होगा। अमेरिका कृषि उत्पादों, मांस और कारों पर आयात शुल्क कम करने के लिए कह सकता है। साथ ही, भारी मात्रा में तेल, गैस और हवाई जहाजों की खरीद के लिए भी दबाव डाल सकता है।

इस दौरान भारत भी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो जाए। भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2024 में करीब 129 अरब डॉलर का व्यापार हुआ जिसमें भारत को 45.7 अरब डॉलर का सर प्लस मिला। भारत ने अमेरिका से आयात के अंतर को मौजूदा 13 प्रतिशत से घटकर चार प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है ताकि भारत को भविष्य की टेरिफ बढ़ोतरी से छूट मिल सके।

इस बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर एक सफल समझौते की उम्मीद बन रही है। 9 जुलाई से अमेरिका द्वारा पारस्परिक टैरिफ लागू होने से पहले भारत टेरिफ पर अंतरिम व्यवस्था के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, लेकिन डेयरी और कृषि को जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बातचीत के दायरे से बाहर रखना चाहता है।

भारत अमेरिका द्विपक्षी व्यापार समझौते के पहले चरण में तेजी लाने के लिए 17 मई से 20 मई तक अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा पर गए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मैं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर दोनों देशों के बीच हुई चर्चा को उर्वर बताया है।मालूम हो की पारस्परिक डायरीज योजना के तहत अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत टेरिफ लगाया था, लेकिन इस पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की थी जो 8 जुलाई की मध्य रात्रि को समाप्त हो रही है। भारत उच्च टैरिफ से बचने और निर्यात बाजार की रक्षा करने के लिए अमेरिका के साथ अपने हितों को आगे करते हुए समझौते के लिए उत्सुक है।

भारत भले ही अमेरिका के साथ संबंध गहरे करना चाहता हो, लेकिन उसे एकतरफा समझौता नहीं करना चाहिए। कुछ ही दिन पहले, जब भारत–पाकिस्तान के बीच तनाव था, तब ट्रंप ने दोनों देशों को समान अहमियत दी। उन्होंने आतंकवाद का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को कूटनीतिक समर्थन दिया और आर्थिक मदद की। भारत के लिए संदेश साफ है – राष्ट्रीय हितों पर ध्यान दिया जाए, राजनीतिक दिखावे पर नहीं। किसी भी समझौते में भारत को अपने प्रमुख क्षेत्रों की रक्षा करनी चाहिए और निष्पक्षता पर जोर देना चाहिए। बातचीत ताकत से होनी चाहिए, मजबूरी में नहीं। देश को आत्मनिर्भर बनाने की गरज से स्वावलंबी अभियान चला रहे स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि भारत उत्पादन के मोर्चे पर सक्षम है। भारत को व्यापार के मोर्चे पर अमेरिका सहित दुनिया के देशों के तनकर खड़ा होना चाहिए, तथा भारतीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए सहमति समझौते करना चाहिए। ❑❑

पानी और खून एक साथ कैसे बहेगा?

सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रवैया पाकिस्तान के लिए साफ संदेश है कि अब सीमा पार आतंकवाद पर गोलमोल बातें नहीं चलेंगी। इस्लामाबाद को पानी चाहिए तो उसे आतंकियों को समर्थन देने की नीति छोड़नी होगी। पानी और आतंकवाद साथ–साथ नहीं बह सकता।

मालूम हो कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 पर्यटकों की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की ओर से हत्या के बाद भारत ने पड़ोसी देश के खिलाफ कई कदम उठाए थे। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया गया था।

उल्लेखनीय है कि 1965, 1971 और वर्ष 1999 के करगिल युद्ध के दौरान भी सिंधु जल समझौता जारी रहा था। पाकिस्तान को भ्रम हो गया था कि उसकी तरफ से उकसावे की चाहे जितनी भी कार्रवाई हों, पानी तो मिलता रहेगा। लेकिन, पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने नई दिल्ली के सब्र का बांध तोड़ दिया। बॉर्डर पर समझौते के बाद पाकिस्तान चाहता है कि सिंधु जल संधि भी बहाल हो जाए, पर विदेश मंत्री जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा है कि पहले सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा।

इस्लामाबाद को पानी चाहिए तो उसे आतंकियों को समर्थन देने की नीति छोड़नी होगी। पानी और आतंकवाद साथ–साथ नहीं बह सकता है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

वैसे भी बात इस संधि को निलंबित रखने या बहाल करने भर की नहीं है, वक्त है इसे पूरी तरह रिव्यू करने का। दोनों देशों के बीच 1960 में यह समझौता हुआ था। भारत ने मानवता दिखाते हुए पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा पानी की बात मान ली थी। सिंधु का 70 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को मिलता है और उसकी 80 प्रतिशत खेती व करीब एक तिहाई हाइड्रो पावर प्रॉजेक्ट इसी पर निर्भर हैं।

1960 से अब तक हालात काफी बदल चुके हैं। आज दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। पानी और ऊर्जा की उसकी अपनी जरूरतें हैं। पुराने समझौतों के आधार पर ट्रीटी जारी रखना न तो संभव होगा और न सही ही।

संधि में कोई भी बदलाव आपसी रजामंदी से ही किया जा सकता है। इसी वजह से भारत ने पहले भी प्रस्ताव रखा था कि संधि पर नए सिरे से बात की जाए, पर पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे वह जम्मू–कश्मीर की किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर एतराज जताता रहा है। वह इस मामले को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जा चुका है।

पाकिस्तान की मांग एकतरफा है। वह चाहता है कि सिंधु में पानी बहता रहे, लेकिन न तो जल के उचित बंटवारे पर बात हो और न आतंकवाद पर उसे कोई आवश्यक कार्रवाई

करनी पड़े। उसने शिमला समझौता समेत दूसरे द्विपक्षीय समझौतों को न मानने की भी धमकी दी है। उसके अड़ियल रवैये से तनाव बढ़ेगा ही और नुकसान भी उसे ही ज्यादा होगा।

अब जबकि भारत और पाकिस्तान युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं, लेकिन भारत ने दो टूक शब्दों में यह संदेश दिया है कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा।

आजादी के बाद कई ऐसे मौके आए जब सिंधु जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक विवाद चला। आखिरकार, 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल समझौता हुआ। उसके बाद से अब तक दोनों देशों के बीच जो भी युद्ध हुए, उसमें भी इस सधि पर आंच नहीं आई थी। लेकिन इस बार भारत सरकार कोई भी लचीला रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका खुला संकेत दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता।

1960 में हुए सिंधु जल समझौते की अहमियत, इसे लेकर दोनों देशों के बीच चले विवाद, इस विवाद की जड़ और राजनीतिक–कानूनी पहलुओं को समझकर ही अब आगे बढ़ना चाहिए।

हिमालय से निकलने वाली यह नदी भारत में जम्मू–कश्मीर और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। 65 साल पहले हुए सिंधु जल समझौते को दुनिया की सबसे कामयाब संधियों में शामिल किया जाता है।

सिंधु नदी बेसिन एक बड़ी नदी प्रणाली है जो तिब्बत से निकलकर भारत–पाकिस्तान अफगानिस्तान और चीन में बहती है। यह लगभग 11 लाख 65 हजार 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से होकर बहती है। सिंधु नदी की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज के साथ–साथ गिलगिट काबुल, स्वात, खुर्रम, टोची, गोमल, संकर, नुब्रा और श्योक भी शामिल है।

आजादी के बाद से ही इसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद था। इसे खत्म कराने के लिए वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें निर्धारित किया गया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का जल भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाएगा। इसमें तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब तथा झेलम को भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया तथा तीन पूर्वी नदियों रावी, व्यास एवं सतलज को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया। इसका अर्थ यह है कि 80 प्रतिशत जल पाकिस्तान को चला गया जबकि शेष 20 प्रतिशत जल भारत के उपयोग के लिए रहेगा। इसके लिए दोनों देशों को एक अस्थाई सिंधु आयोग के गठन का प्रावधान था जिसकी वार्षिक बैठक अनिवार्य बनाई गई थी।

समझौते के कुछ साल बाद ही इस पर सवाल उठने लगे थे। इस समझौते के रिव्यू के लिए भारत में जोरदार मांग हुई। यह भी पूछा जाने लगा कि 1960 में किस वजह से भारत ने विवाद को खत्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता स्वीकार की? यह भी कि वैश्विक वित्तीय संस्थान की मदद लेने को पाकिस्तान क्यों राजी हुआ? सवाल यह भी है कि वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता की प्रक्रिया में शामिल होने का कारण क्या था?

जानकार बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने तत्कालीन राजनीतिक वजहों से वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता मंजूर की थी। और यह भी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को इस समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इस सधि के तहत सिंधु आयोग बनाया गया, जिसका इसे लागू करने में बड़ा योगदान रहा है। संधि होने के बाद पूर्व में दोनों देशों के बीच पांच बड़े विवाद हुए जिसे सुलझाने में दोनों पक्ष कामयाब रहे। सिंधु आयोग की भी विवादों को सुलझाने में बड़ी भूमिका रही है।

लेकिन आज वर्ष 2025 में जब हम इस समझौते की ओर नजर डालते हैं तो सबसे बड़ी जरूरत जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों के आकलन की है। जब समझौता हुआ था, तब दुनिया को जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली दुश्वारियों का ख्याल दूर–दूर तक नहीं था, जबकि आज यह बड़े संकट के रूप में उभरा है। भारत और पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में इसी वजह से एक्स्ट्रीम वेदर पैटर्न दिख रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर जान–माल का नुकसान भी हुआ है।

भारत इस पानी का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान को दिया लेकिन उसके साथ जल संधि को लेकर नाराजगी का इजहार करता आया है। उसे लगता है कि समझौते में ज्यादातर इंसाफ नहीं हुआ। 2023 में भारत ने पाकिस्तान से इसमें संशोधन के लिए कहा था, लेकिन बात नहीं बनी। अब जबकि भारत ने सधि को सस्पेंड कर दिया है तो इस बारे में आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच जरूर बात होनी चाहिए और तब भारत की सरकार इसमें तब्दीली का मुद्दा जोर शोर से उठा सकती है। सरकार समझौते को एकतरफा साबित करते हुए कम से कम बराबरी का हिस्सा यानी 50 प्रतिशत पानी अपने लिए सुरक्षित कर सकती है। पहलगाम की घटना के बाद सरकार ने समझौते को स्थगित करके इसका संकेत दिया है कि भारत पूर्व के फैसलों से संतुष्ट नहीं है। ❑❑

युद्धः विनाश का वैश्विक व्यापार और मानवता का सवाल

युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास का एक दुःखद लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक, भले ही युद्धों के स्वरूप बदलते रहे हों, परंतु उनके मूल कारण आज भी वही हैं – सत्ता की लिप्सा, प्रभुत्व की चाह और संकुचित राष्ट्रवाद। महाभारत का महासंग्राम हो या प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, हर संघर्ष के बाद शेष रह जाती हैं, केवल लाशें, उजड़े नगर, बिखरे सपने और मानवता की हार।

विडंबना यह है कि आज जब विज्ञान और तकनीक नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, तब भी दुनिया युद्ध के उन्माद से ग्रस्त है, संकुचित राष्ट्रवाद का ज्वर चढ़ा है, हर देश दूसरे को आंखें दिखा रहा है, मानो एक–दूसरे के खून का प्यासा हो गया हैं। परिस्थितियां धीरे–धीरे तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही हैं।

युद्ध को कई बार राष्ट्र की अस्मिता से जोड़ दिया जाता है। युद्ध के पहले ऐसी परिस्थितियां तैयार की जाती हैं कि शांति और सह–अस्तित्व में विश्वास रखने वाले लोग भी युद्ध के समर्थन में खड़े हो जाते हैं।

– विवेकानंद माथने

यूक्रेन, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, अब नाटो से जुड़ना चाहता है। नाटो ने रूस को घेरने की मंशा से यूक्रेन का समर्थन किया और यह टकराव युद्ध में बदल गया। यह संघर्ष तीन साल से जारी है।यूक्रेन के शहर खंडहरों में तब्दील हो गए और बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो गए। अब तक दोनों पक्षों के कुल 1.90 लाख से अधिक सैनिक मारे गए और 2.80 लाख से अधिक घायल हुए हैं। यूक्रेन के 1.43 करोड़ आबादी विस्थापित हो चुकी हैं, जिनमें से 65 लाख से अधिक शरणार्थी बनकर विदेश चले गए और शेष अपने ही देश में दर–दर भटक रहे हैं।

हमास द्वारा इज़राइल पर हमले और नागरिकों को बंधक बनाए जाने के जवाब में इज़राइल ने गाज़ा पर भीषण हमला किया। इस बदले की आग में हज़ारों निर्दोष लोगों की जान गई और लाखों घायल हुए हैं। जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाज़ा के करीब 19 लाख लोग विस्थापित हो चुके है। 70 प्रतिशत से अधिक आवास नष्ट हो चुके हैं, और अस्पताल, स्कूल, जल और बिजली व्यवस्था का लगभग 90 प्रतिशत ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। भोजन और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों का भी गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। लेबनान और यमन भी युद्ध के चपेट में आ गये।

यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा चुकी है, वहीं पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस की अर्थव्यवस्था भी गंभीर दबाव में है। गाज़ा पूरी तरह तबाह हो चुका है। युद्ध का नतीजा यही है कि इन देशों की जनता को विकास नहीं, बल्कि केवल विनाश और विस्थापन का बोझ ढोना पड़ रहा है।

सूडान में 2023 से सेना और आरएसएफके बीच जारी संघर्ष में 61,000 से अधिक लोग

मारे गए और 1.2 करोड़ विस्थापित हुए। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद गृहयुद्ध छिड़ा, जिसने लाखों को शरणार्थी बना दिया। यमन में 2014 से जारी युद्ध ने 68 प्रतिशत आबादी को मानवीय सहायता पर निर्भर कर दिया। इथियोपिया में तिग्राय संघर्ष ने हजारों की जान ली और लाखों को भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया। इराक और अफगानिस्तान के ज़ख्म आज भी हरे हैं।

हर युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम आदमी चुकाता है। जान–माल के नुकसान के साथ–साथ आम जीवन की बुनियादी ज़रूरतें और सामाजिक प्रगति भी बुरी तरह प्रभावित होती है। सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी–उन्मूलन जैसे जनकल्याणकारी क्षेत्रों के बजट में कटौती कर रक्षा खर्च बढ़ा देती हैं, जिससे आम जनता का जीवन और भी कठिन हो जाता है। भूख, बेरोजगारी और असमानता बढ़ती है।

युद्ध का अंजाम केवल विनाश होता है, फिर भी युद्ध क्यों जारी रहते हैं? इसे क्यों नहीं रोका जाता? आखिर कौन हैं वे, जो युद्ध से लाभ उठा रहे हैं? दरअसल, युद्ध केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं होता, यह एक सुनियोजित योजना का हिस्सा होता है, जिसमें कुछ ताकतें पर्दे के पीछे से भारी लाभ उठाती हैं।

युद्ध के पीछे असली कारण संसाधनों पर कब्जा, हथियारों की बिक्री बढ़ाना, मंदी से जूझती अर्थव्यवस्था को गति देना, और सत्ता को मजबूत करना होता है। तेल, खनिज, जल, जमीन और श्रम, इन पर नियंत्रण पाने के लिए बार–बार लड़ाइयां लड़ी गई हैं। अमेरिका, यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा यूक्रेन को हथियार देना एकतरफा सहायता नहीं है, बल्कि इसके पीछे यूक्रेन के संसाधनों और क्षेत्रीय प्रभाव पर पकड़ बनाने का रणनीतिक लक्ष्य था।

इन युद्धों ने पुराने हथियारों के भंडार खाली कर दिए। साथ ही, एआईड्रोन, हाईपरसोनिक मिसाइलें और साइबर हथियार जैसे नई तकनीकों वाले हथियार भी आज़माए गए। युद्ध एक 'लाइव टेस्टिंग लैब' बन चुका है, जहां नए हथियारों की कार्यक्षमता को परखा गया है और उनके लिए वैश्विक बाज़ार तैयार किया गया है।

अब वैश्विक दौड़ शुरू हुई हैं। सभी देश इन हथियारों की दौड़ में शामिल हो रहे है। इससे रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा बाजार खड़ा हुआ है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी जैसे देश सबसे बड़े हथियार निर्यातक हैं। युद्ध उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर रहा है।

हथियार व्यापार एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। पारंपरिक हथियारों से लेकर परमाणु, जैविक और अब एआई आधारित स्मार्ट हथियारों तक, यह उद्योग युद्ध पर ही टिका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च 2. 70 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं जब भी आर्थिक संकट और मंदी से गुजरती हैं। तब युद्ध उनके लिए एक अवसर बन जाता है, हथियारों की खपत बढ़ती है, पुराना स्टॉक खाली होता है और नए उत्पादनों का बाजार तैयार होता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देश पुराने हथियारों को युद्ध में झोंककर अपनी सैन्य उत्पादन प्रणाली को पुनर्जीवित करते हैं। यह युद्ध उनके आर्थिक पुनरुद्धार की रणनीति बन जाता है।

हाल की पहलगाम जैसी आतंकी घटनाएं निस्संदेह बहुत पीड़ादायक हैं, लेकिन यह भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या इन हमलों के पीछे कोई बड़ी ताकतें दोनों देशों को युद्ध के रास्ते पर धकेलना चाहती है? जनता का आक्रोश जायज़ होते हुए भी, यह प्रश्न जरूरी है कि क्या ये हमले केवल आतंकियों के हैं, या कोई और ताकतें इन्हें अंजाम देकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की ज़मीन तैयार कर रही हैं?

वे जानते है कि कोई भी बड़ा देश आम जनता के समर्थन के बिना युद्ध नहीं कर सकता। पहलगाम जैसे आतंकी हमलों से उत्पन्न हुई संवेदनशीलता का दोहन करना आसान होता है। युद्ध कई बार राष्ट्र की अस्मिता से जोड़ दिया जाता है। युद्ध के पहले ऐसी परिस्थितियां तैयार की जाती हैं कि शांति और सह–अस्तित्व में विश्वास रखने वाले लोग भी युद्ध के समर्थन में खड़े हो जाते हैं।

युद्धोन्माद फैलाने तथा लड़ने के लिए दो देशों को उकसाने में कॉर्पोरेट मीडिया और सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। फेक न्यूज़, उग्र भाषण और भावनात्मक उन्माद फैलाकर जनता को युद्ध के समर्थन में खड़ा कर दिया जाता है। लोग भ्रमित होकर प्रतिशोध की आग में युद्ध को न्याय समझने लगते हैं। लगता है कि युद्ध को बढ़ावा देने वाली शक्तियां अपने उद्देश्य में सफल होती जा रही हैं।

यदि यह उन्माद नहीं रुका और यह तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ा, तो निश्चित है कि जैविक, परमाणु और एआई आधारित विध्वंसक प्रणालियों का प्रयोग होगा। यह ऐसी तबाही ला सकता है जिसकी कल्पना भी भयावह है और जिसके परिणाम पूरी मानवता को सदियों तक भुगतने पड़ेंगे।

इसलिए जरूरी है कि हम युद्धोन्मादी नेताओं, उकसाने वाले मीडिया संस्थानों और हथियार बेचने वाले देशों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध को ही चुनौती दें। यह लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वे युद्ध को नकारें और शांति का रास्ता चुनें। विनाश नहीं, जीवन चुनें!❑❑

अब पाकिस्तान के साथ बेटी व्यवहार बंद करें भारतीय मुसलमान

14–15 अगस्त 1947 के दरमियान भारत के दो टुकड़े हुए ! टुकड़े शब्द का प्रयोग इसलिए प्रासंगिक है कि भारतवर्ष का स्वतः विभाजन न होकर इस्लामिक साजिश के तहत इसे जबरन दो भागों में बांटा गया है? 2 जून 1947 को भारत के अंतिम वायसराय एडमिरल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने घोषणा की थी कि "ब्रिटेन ने यह स्वीकार कर लिया है कि देश को मुख्यतः 'हिंदू भारत' और 'मुस्लिम पाकिस्तान' में विभाजित किया जाना चाहिए , जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) और पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के भौगोलिक रूप से अलग–अलग क्षेत्र शामिल होंगे'। ऐसा नहीं हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में दो देश की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण समझौते की मूल भावना के अनुरूप नहीं हुआ। 'हिंदू भारत' के साथ धोखा हुआ।

चलो एक बार, सनातन संस्कृति का अनुपालन करते हुए 'बीती ताहि बिसार दे , आगे की सुधि लें', के आलोक में मामला खत्म हो जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। एक ओर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भारत में फिरकापरस्त लोगों के साथ मिलकर रेडिकल इस्लाम और आतंकवाद को बढ़ावा देकर इस्लामिक स्टेट तैयार करने की साजिश रची।

रेडिकल इस्लाम चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता है, जो हिंसा, धार्मिक कट्टरता, युवाओं का ब्रेन वॉस, आर्थिक–सामाजिक असमानता को जायज ठहराती है । वहीं दूसरी ओर, नेहरू–गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता में रहते हुए कश्मीर नीति, जिसमें कश्मीर को विशेष दर्जा जैसे कई दूरगामी कष्ट देने वाले निर्णय से मुस्लिम कश्मीरियों का पाकिस्तान परस्ती प्रेम पनपता गया और आज चरम सीमा पर पहुंच गया है।

दो दुश्मन देश के बीच बेटी व्यवहार, प्रेम भाव के नाम पर चल रहा कार्य व्यापार एक जटिल मुद्दा बन गया है, जिसके पीछे ऐतिहासिक, राजनीति, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक कारण है जिसने कश्मीरियों को पाकिस्तान के नापाक इरादों के साथ जोड़

कश्मीरी मुसलमान के साथ–साथ देश के अन्य मुसलमानों को भी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में दुश्मन देश के साथ बेटी व्यवहार पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और हो सकते तो पाकिस्तान के साथ बेटी–व्यवहार बंद कर देना चाहिए।

– डॉ बालाराम परमार 'हंसमुख'

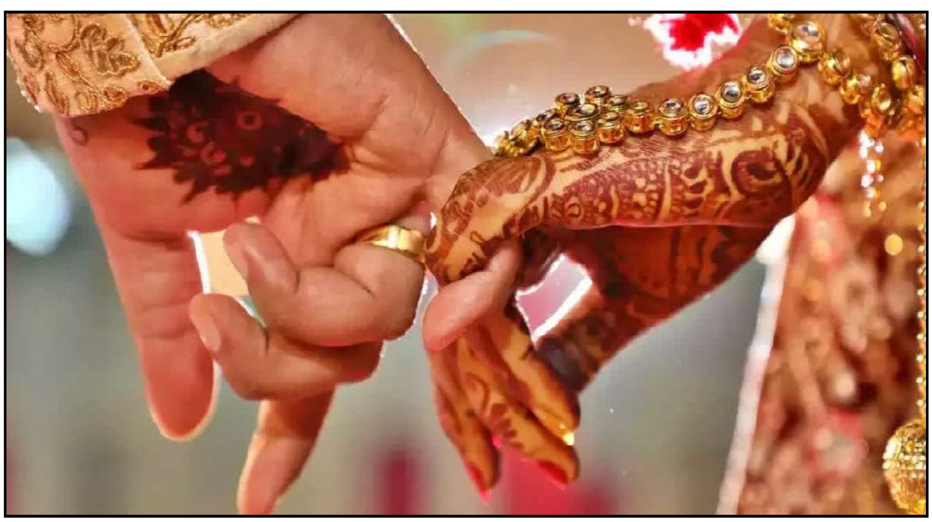

रखा है। कश्मीरी अलगाववादियों का पाकिस्तान के प्रति आकर्षण ही दोनों देशों के बीच मुसीबत का कारण है।

पाकिस्तान का हिंदुस्तान के प्रति नफरत भरा रवैया विभाजन के समय हुए रक्तपात और हिंसा, पाक अधिकृत कश्मीर, बलुचों पर जोर जबरदस्ती, पाकिस्तान में अधिकांश समय सैन्य शासन और राजनीतिक अस्थिरता तथा रेडिकल इस्लाम से प्रभावित मीडिया और मदरसा आधारित शिक्षा प्रणाली के चलते है। इससे भारत के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता रहा है।

आजादी के बाद से मुसलमान बेटियों का पाकिस्तान में शादी करना और पाकिस्तान की बेटियों का हिंदुस्तान में शादी करने के अनवरत सिलसिले में इस्लामिक स्टेट तैयार करने की साजिश दिखाई पड़ती है ! क्योंकि दो दुश्मन देश के बीच बेवजह विवाह संपन्न होने से सुरक्षा जोखिम बढ़ जाता है। खासकर एक दुश्मन देश की जासूसी एजेंसियां दूसरे देश की सामरिक जानकारी प्राप्त करने में प्री–वेडिंग समारोह, वेडिंग सेरेमनी, वलीमा आदि के समय रेकी के रूप में करता है। भारत सरकार का राष्ट्र हित में असहज निर्णय एवं युद्ध की स्थिति में राजनीतिक तनाव के साथ–साथ पारिवारिक तनाव भी दोनों देशों में बेटी–दामाद के घर–आंगन बढ़ जाता है। जिससे भावनात्मक सामाजिक दबाव और कानूनी जटिलताएं दंपति के दांपत्य जीवन में खलल डालती रही है। क्योंकि उन्हें अपने परिवार और समाज का उस स्तर पर समर्थन नहीं मिलता है। जिस तरह ऐसे संवेदनशील मौके पर अमूमन मिलना चाहिए।

दुर्भाग्य से रेडिकल इस्लाम की मानसिकता के चलते दोनों देशों की दंपति और उनके परिवार इन चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान ढूंढने की बजाय दोनों देशों के राजनीतिक खट्टे– मीठे रिश्तों से जोड़कर भारत को कमजोर करने का प्रयास करते हैं।

इसी तरह के कई और दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुश्मन देश के बीच विवाह व्यक्तिगत पसंद, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और दो परिवारों के बीच प्यार–मोहब्बत और महिला सशक्तिकरण का कारण नहीं बन पाता है। अतः कश्मीरी मुसलमान के साथ–साथ देश के अन्य मुसलमान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में दुश्मन देश के साथ बेटी व्यवहार पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बेटी व्यवहार बंद कर देना चाहिए।

वर्तमान में सरकार ने जिस कड़ाई के साथ सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के लिए रोकने का ऐलान किया है, भारतीय परिवारों को भी आगे आना चाहिए तथा एकजूट होकर यह फैसला करना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से भारत के खिलाफ आतंक की कार्यवाही पूरी तरह समाप्त नहीं करता, भारतीय मुसलमान (विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ) अपना बेटी व्यवहार का सिलसिला सख्ती के साथ बंद रखेंगे। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http:// swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

सेना के साथ खड़ा भारत, सत्ता के लिए लड़ता पाकिस्तान

हाल के वर्षो में भारतीय राजनीति में जिस तरह से सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हर मुद्दे पर तलवारें खींची नजर आती थी, उसके ठीक उलट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में राजनीतिक एकजुटता देखने को मिली है, उससे देश की आम जनता काफी खुश है, वहीं पाकिस्तान में इसके उलट नजर आ रहा है। पड़ोसी मुल्क में विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोसने और उन्हें नाकाबिल नेता साबित करने में लगा है। दोनों देश की सेनाओं की तुलना शेर और सियार के रूप में की जा रही है।

बहरहाल, भारत के लिये यह सुखद है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर कदम पर विपक्ष बिना किसी शर्त के पूरी मजबूती से खड़ा है। जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक अद्‌भुत परिवर्तन देखा गया है। विपक्षी दलों ने इस बार न केवल सरकार का समर्थन किया बल्कि सेना के साहस और कार्रवाई की खुलकर सराहना की। इससे पहले उरी और पुलवामा हमलों के बाद जिस तरह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे, और बीजेपी ने उन्हें राष्ट्र विरोधी खांचे में रखकर सियासी नुकसान पहुंचाया था, उस पृष्ठभूमि में यह बदलाव बेहद अहम है। यह न केवल राजनीति की परिपक्वता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत अब एक स्वर में बोल रहा है।

गौरतलब हो, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले ने न केवल आम जनता की भावनाओं को आहत किया, बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर दी थी कि वे इस मुद्दे को किस रूप में लें। कांग्रेस और अन्य प्रमुख दलों ने बिना देर किए केंद्र सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने सुरक्षा और खुफिया तंत्र की संभावित चूक का मुद्दा उठाने के बावजूद, इसे राजनीति का विषय नहीं बनने दिया। यह देश की एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए विपक्ष का एक परिपक्व और जिम्मेदार रवैया था।

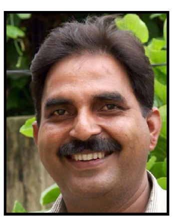

इस समय पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा भारत से नहीं, बल्कि अपनी बिखरे हुई राजनीतिक नेतृत्व और कमजोर रणनीतिक सोच से है।

– संजय सक्सेना

भारतीय सेना ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक और प्रभावशाली कार्रवाई की। सेना की इस जवाबी कार्रवाई को विपक्ष की ओर से न केवल समर्थन मिला बल्कि सराहना भी हुई। कोई सवाल नहीं, कोई प्रमाण की मांग नहीं, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं बस एक सुर में सरकार और सेना के साथ खड़े रहने की भावना। 'भारत माता की जय' और 'जय हिंद' के नारों के साथ विपक्षी नेता भारतीय सेना के साथ नजर आए। यह एक ऐसी तस्वीर थी जो 2016 के उरी हमले या 2019 के पुलवामा हमले के बाद नजर नहीं आई थी।

उरी हमले के बाद जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उस पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी के तौर पर पेश करके राजनीतिक लाभ उठाया था। ठीक ऐसा ही पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान हुआ था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सबूत मांगे थे, जिसके चलते उनकी पार्टी को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी ने भी सेना के शौर्य पर विश्वास जताने के साथ–साथ प्रधानमंत्री पर जवानों के बलिदान की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इन बयानों से कांग्रेस को चुनावी मैदान में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार कहानी बदली हुई है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को रोक दिया, पार्टी की सर्वोच्च नीति–निर्धारण संस्था कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक बुलाई गई और राहुल गांधी ने स्वयं सेना को समर्थन देने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के सुझाव पर कांग्रेस ने अपनी 'संविधान बचाओ' रैली स्थगित कर दी, ताकि सेना के प्रति एकजुटता और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश स्पष्ट रूप से जाए। यहां तक कि कर्नाटक कांग्रेस ने भी अपनी उस सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया, जिसमें शांति को सबसे बड़ा हथियार बताया गया था जो शायद मौजूदा माहौल में सेना के ऑपरेशन के संदर्भ में गलत संदेश दे सकती थी।

कांग्रेस के इस नए रुख के साथ ही अन्य विपक्षी दल भी उसी दिशा में नजर आए। एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बात करके अपनी पार्टी का पूरा समर्थन देने की घोषणा की। यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे ए के एंटनी, जो अक्सर केंद्र सरकार के आलोचक रहे हैं, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर को 'एक मजबूत शुरुआत' बताया और सेना की निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी के शब्दों की आलोचना कर चुके थे, उन्होंने भी इस बार सेना के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरा देश एकजुट है।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर सराहना की और जवानों को सलाम किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अक्सर केंद्र सरकार के आलोचक रहते हैं, उन्होंने भी इस बार सरकार के सुर में सुर मिलाया और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई की प्रशंसा की। यहां तक कि वामपंथी दलों ने, जो आमतौर पर सैन्य कार्रवाई पर संयम बरतने की बात करते हैं, उन्होंने भी पहलगाम हमले के बाद सरकार और सेना के साथ खड़े होने की बात कही। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने भी माना कि इस बार भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

यह पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति के लिए एक नई दिशा का संकेत है। यह दर्शाता है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे पर अब राजनीतिक दल न केवल एकजुट हैं, बल्कि अपने पुराने सियासी रवैये की भी समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस का यह नया रुख जहां उसे राष्ट्रवादी विमर्श में खुद को फिट करने में मदद करेगा, वहीं अन्य विपक्षी दलों के लिए भी यह संदेश है कि जनता अब केवल आरोप–प्रत्यारोप नहीं, बल्कि एकजुटता और जिम्मेदारी की राजनीति देखना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति न तो नरम है, न ही विभाजित। यह केवल केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि विपक्ष की परिपक्व भागीदारी का भी प्रतिबिंब है। अगर इस रुख को भविष्य में भी कायम रखा गया, तो यह न केवल देश की आंतरिक राजनीति को परिपक्व बनाएगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत की छवि को और सुदृढ़ करेगा।

बात पाकिस्तान की कि जाये तो वहां सेना,सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हुई हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सैन्य और रणनीतिक स्थिति डगमगाई हुई है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सियासत भी बुरी तरह बिखर गई है। जब देश को एकजुट होकर संकट का सामना करना चाहिए, तब पाकिस्तानी नेता एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच बढ़ती खींचतान ने पूरे मुल्क को असमंजस में डाल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने मौजूदा सरकार पर सेना के साथ मिलीभगत और गलत फैसलों का आरोप लगाया है, वहीं सरकार का कहना है कि इमरान खान जैसे नेता युद्ध के समय भी राष्ट्रविरोधी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा है। संसद में तीखी बहस के दौरान विपक्षी नेताओं ने सेना की विफलताओं पर सवाल खड़े किए, जिससे देश की अंतरराष्ट्रीय छवि और कमजोर हुई। इस बीच, पाकिस्तानी सेना और सरकार के बीच भी समन्वय की कमी साफ नजर आयी। मीडिया में लीक हो रही जानकारियों के मुताबिक, कई रक्षा फैसलों पर सेना और सरकार की राय अलग–अलग रही है। जिससे फ्रंट पर रणनीतिक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इससे उस देश के आम नागरिकों में असुरक्षा और निराशा का माहौल है। जानकार मानते हैं कि इस समय पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा भारत से नहीं, बल्कि अपनी बिखरी हुई राजनीतिक नेतृत्व और कमजोर रणनीतिक सोच से है। ❑❑

रुपए की बढ़ती ताकत एवं भारत में बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार

फरवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत सबसे निचले स्तर अर्थात 87.44 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई थी। इसके बाद धीरे–धीरे इसमें सुधार होता हुआ दिखाई दिया है एवं अब दिनांक 30 अप्रैल 2025 को यह 84.50 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं दिनांक 18 अप्रैल 2025 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ 68,610 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है और यह दिनांक 27 सितम्बर 2024 के उच्चतम स्तर 70,489 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर के बहुत करीब है। भारतीय रुपए की मजबूती एवं विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब विश्व के समस्त देश अमेरिकी प्रशासन के टैरिफ युद्ध का सामना करते हुए संकट में दिखाई दे रहे हैं। परंतु, भारत पर टैरिफ युद्ध का असर लगभग नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है। यह भी सही है कि हाल ही के समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर पर दबाव बढ़ा है और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स लगभग 109 के स्तर से नीचे गिरकर दिनांक 30 अप्रेल 2025 को 99.43 के स्तर पर आ गया है। शायद अमेरिका भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को कम करना चाहता है ताकि अमेरिका में आयात महंगे हों एवं अमेरिकी निर्यातकों को अधिक लाभ पहुंचे। परंतु, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर पर दबाव के बढ़ने से सोने की कीमतों में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हुई है और यह दिनांक 22 अप्रैल 2025 को अपने उच्चतम स्तर 3500 अमेरिकी डॉलर प्रति आउन्स पर पहुंच गई थी। साथ ही, अमेरिकी शेयर बाजार भी धराशायी हुआ है और वहां के डाउ जोंस एवं अन्य इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज हुई है। अब ऐसा आभास हो रहा है कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों के विरुद्ध छेड़े गए टैरिफ युद्ध का विपरीत असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर होता हुआ दिखाई दे रहा है।

भारत में आंतरिक मजबूती के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।

–प्रहलाद सबनानी

भारतीय रुपए के मजबूत होने के चलते भारतीय शेयर (पूंजी) बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक एक बार पुनः अपना निवेश बढ़ाने लगे हैं एवं पिछले लगातार कुछ दिनों से इन विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में शेयरों की भारी मात्रा में खरीद की है। जबकि, सितम्बर 2024 के बाद से विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार अपना निवेश निकाल रहे थे और इस बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री भारतीय शेयर बाजार में की है। जिसके चलते भारतीय शेयर बाजार के निफ्टी इंडेक्स में लगभग 3500 अंकों की भारी गिरावट दर्ज हुई थी। परंतु, भारतीय संस्थागत निवेशकों, भारतीय म्यूचअल फण्ड एवं खुदरा निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में अपना निवेश बढ़ाकर भारतीय पूंजी बाजार को सम्हालने में मदद की है अन्यथा भारतीय शेयर बाजार धराशायी हो गया होता। परंतु, अब भारतीय शेयर बाजार में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है एवं अब एक बार पुनः यह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल के समय में निफ्टी इंडेक्स में लगभग 1500 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत के विदेशी व्यापार में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। विभिन्न देशों को भारत से निर्यात 5.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 82,093 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गए हैं वहीं अन्य देशों से भारत में होने वाले आयात 6.85 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 91,519 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गए हैं। निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि दर अधिक रही है जिसके चलते भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 9,426 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। व्यापार घाटे के बढ़ने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ा और रुपया कमजोर हुआ। भारत में कच्चे तेल एवं स्वर्ण का आयात भारी मात्रा में होता है। मुख्य रूप से इन्हीं दो मदों की कीमतें भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ीं थी, जिसका प्रभाव भारत में अधिक आयात के रूप में दिखाई दिया है। परंतु, अब हर्ष की बात है कि कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में 75 अमेरिकी डॉलर प्रति बेरल से घटकर लगभग 65 अमेरिकी डॉलर प्रति बेरल पर नीचे आ गई है और स्वर्ण के महंगे होने के चलते स्वर्ण का आयात भी कुछ कम हुआ है। उक्त दोनों घटनाओं के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए पर दबाव कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में भले स्थितियां ठीक नहीं दिखाई दे रहीं है, परंतु भारत में आंतरिक मजबूती के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, स्टैंडर्ड एवं पूअर आदि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थानों ने भी वित्तीय वर्ष 2025–26 में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में विकसित हो रही विपरीत परिस्थितियों के बीच भी, भारतीय अर्थव्यवस्था के 6 प्रतिशत से अधिक की दर से आगे बढ़ने की सम्भावना व्यक्त की है। जबकि यूरोप के कुछ देशों यथा जर्मनी, कनाडा आदि एवं ब्रिटेन तथा अमेरिका में मंदी की सम्भावनाएं स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में तो वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही (जनवरी–मार्च 2025) में आर्थिक विकास दर में 0.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। लगभग यही हाल यूरोप के कई देशों तथा जापान आदि का है। चीन की आर्थिक विकास दर में भी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। यदि जापान एवं जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2025 एवं 2026 में गिरावट दर्ज होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था 6 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर लेती है तो बहुत सम्भव है कि वर्ष 2025 में जापान एवं वर्ष 2026 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व में अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपरीत परिस्थितियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से आगे बढ़ने के पीछे भारत की आंतरिक मजबूती मुख्य है। भारत में अभी हाल ही में महाकुम्भ मेला सम्पन्न हुआ है, इस महाकुम्भ में लगभग 66 करोड़ भारतीय मूल के नागरिकों ने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। इतनी भारी मात्रा में नागरिकों के यहां पहुंचने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल ही मिला है। महाकुम्भ में भाग ले रहे प्रत्येक नागरिक ने औसत रूप से यदि 2000 रुपए भी प्रतिदिन खर्च किए हों और प्रत्येक नागरिक ने औसतन कुल तीन दिवस भी महाकुम्भ में बिताएं हों तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 396,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ पहुंचा है। रोजगार के लाखों अवसर निर्मित हुए हैं, यह अलग लाभ रहा है। आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया गया जिसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक देश को मिलता रहेगा। देश में धार्मिक पर्यटन भी भारी मात्रा में बढ़ा है जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। धार्मिक पर्यटन एवं महाकुम्भ के चलते ही अब यह आंकलन हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी–मार्च 2025) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हो सकती है। ❑❑

ट्रम्प की अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति और भारत

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और व्यापार में फिलहाल हलचल मची हुई है। अमरीका की अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक भूमिका बदल रही है। पहले अमरीका अपने आप को दुनिया का लीडर समझता था और अपनी राजनीति और अपनी अंतरराष्ट्रीय भूमिका उसी ढंग से चलाता था। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद शायद पहली बार यह हो रहा है की अमरीका अपने आप को एक देश के तौर पर देख रहा है और अपने देश के हित की बात कर रहा है। लगता है कि नेतागिरी से अमरीका ऊब चुका है और दूसरों की लड़ाई अब नहीं लड़ना चाहता। यह अमरीका के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन दुनिया के लिए अच्छा हो यह कहा नहीं जा सकता! आज भी दुनिया अमरीकन डॉलर को अंतरराष्ट्रीय चलन के रूप में मानती है और अपने सारे व्यापार–व्यवहार डॉलर में करती है। इतना ही नहीं दुनिया के देश अपनी सारी जमा–पूंजी भी अमरीकन डॉलर में रखते हैं। इसलिए अमरीका को समझदारी से काम लेना होगा।

अमरीका व्यापार घाटा काल्पनिक

अमरीका के नए राष्ट्रपति ट्रम्प सत्ता में आते ही अपनी चुनावी वादे सच करने निकले है। उनका नारा 'अमरीका पहले' का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। यह बात सही है कि 1972 से अमरीका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में घाटा उठा रहा है और यह घाटा 2024 तक 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। और इसमें सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन, मेक्सिको और कनाडा के साथ के व्यापार में है। भारत के साथ यह घाटा45.7 बिलियन डॉलर मतलब 4600 करोड़ रुपए का है। लेकिन यह घाटे की बात एकतरफा है। अमरीका का वस्तु व्यापार, घाटे का है, लेकिन पूंजी–व्यापार फायदे का है। व्यापार घाटे में बाहर गया डॉलर पूंजी के रूप में अमरीका वापस आता है यह बात नहीं भुलाना चाहिए। सभी देश अमरीकी डॉलर पर भरोसा करते है और अपनी जमा पूंजी डॉलर में रखते है यह बात महत्वपूर्ण है। इसलिए अमरीका द्वारा अपने आप को अलग कर सोचना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार को क्षति पहुंचा सकता है।

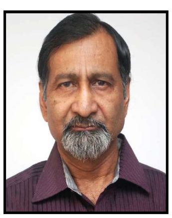

अमरीका को चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपनी मर्जी से प्रभावित करने की कोशिश ना करे, यही सभी के हित में होगा।

–अनिल जवलेकर

अमरीका क्या चाहता है

अमरीका का प्रभाव पहले महायुद्ध के बाद से शुरू हुआ लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद अमरीका पूरी तरह महासत्ता के रूप में सामने आया। सभी दृष्टि से अमरीका ने विकास किया और दुनिया पर राज किया। सभी अंतरराष्ट्रीय समस्याओं में अपनी भूमिका निभाई और सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अपना आर्थिक योगदान दिया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मुक्त करने हेतु हुये सभी करारों में भी आगे रहा। वैसे राष्ट्रवाद अमरीका के लिए कोई नई बात नहीं है। अपना हित ध्यान में रखकर ही अमरीका अपनी राजनीति करता आया है और कमजोर देशों से अपनी बात मनवाता रहा है। लेकिन दुनिया में अब चीन के रूप में एक नई महासत्ता उभरी है और उसने व्यापार के बल–बूते पर अपनी सत्ता जमाई है।

दुनिया के जीडीपी में अमरीका और चीन दोनों को मिलाकर हिस्सा लगभग आधा है। व्यापार में चीन अमरीका से आगे निकल गया है क्योंकि उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार फायदे का रहा है। और यही एक वजह है कि अमरीका को मजबूरन अपने व्यापार नीति को बदलने की जरूरत महसूस हुई। अमरीका चाहता है कि उसके व्यापार घाटे में कमी आए। लेकिन इससे भी ज्यादा वह दुनिया में चीन का प्रभाव कम करना चाहता है और वह तभी हो सकता है जब उत्पादन को चीन से हटाकर किसी दूसरे देशों में ले जाया जाये। अमरीका यह कैसे करेगा यह देखने वाली बात होगी?

भारत और अमरीका का व्यापार

यह सभी जानते है की भारत और अमरीका का रिश्ता पुराना है लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक गुट निरपेक्ष तथा व्यापार में संरक्षणात्मक नीति अपनाई जिसकी वजह से अमरीका और भारत के दरम्यान व्यापार मर्यादित रहा। लेकिन 1991 से भारत ने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारी और उसके चलते दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा। वर्ष 2022–23 तक यह व्यापार 190 बिलियन डॉलर तक (16 लाख करोड़ रुपए) पहुँच गया है। यही नहीं अमरीका भारत का एक सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है।

भारत ने अमरीका के साथ व्यापार में अपने सेवा निर्यात और कम लागत वाली उत्पाद से संतुलन बनाए रखा है और फायदे में रहा है। भारत मुख्यतः रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स (दवा निर्माण और जैविक), पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, कृषि उत्पाद वगैरे का निर्यात करता है तथा कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थ, विमान एवं स्पेस क्राफ्ट के पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी, कृषि उत्पाद वगैरह का अमरीका से आयात करता है। निश्चित रूप से अमरीका के बढ़े हुए आयात शुल्क ने भारत को सदमे में डाला है।

ट्रम्प की व्यापार नीति का भारत पर असर

यह तो निश्चित है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक एक–दूसरे से मिली हुई व्यवस्था है जिसका असर हर एक शामिल देश पर होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देश के आयात और निर्यात पर लगे बंधन और दी गई सुविधाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अमरीका दुनिया का एक बड़ा देश है जिसके साथ व्यापार कर दूसरे देश लाभ कमाते है। भारत भी उसमें है। इसलिए ट्रम्प व्यापार नीति का भारत पर प्रभाव पड़ेगा यह निश्चित है। भारत के निर्यात पर इसका असर होगा और यह असर अमरीका–भारत के व्यापार पर ही नहीं बल्कि भारत के अन्य देशों के व्यापार पर भी पड सकता है। उत्पादन के क्षेत्र में चीन सबसे आगे है और अपना उत्पाद बेचने के लिए वह सस्ता व्यापार करेगा जो भारत के निर्यात को स्पर्धात्मक बनाएगा। यह सही है कि भारत भी इस मौके का फायदा उठा सकता है और अपना उत्पादन क्षेत्र बढ़ा कर निर्यात बढा सकता है। कैसे और कितना यह देखने वाली बात होगी? वैसे भारत ने आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई हुई है जिसका मतलब भारत अपनी अंदुरुनी क्षमता बढ़ाना चाहता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पूंजी पर निर्भरता कम करना चाहता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस दिशा में बनी नीति ही उपयुक्त रहेगी।

ट्रम्प की व्यापार नीति खतरनाक

दुनिया वैश्वीकरण की ओर मुड़ी हुई थी उसमें भी अमरीका आगे था। अब खुद ही संरक्षणात्मक व्यापार की बात कर रहा है। विकसित देशों ने जब तक अपना फायदा हो रहा था खुले व्यापार पर ज़ोर दिया। जब भारत जैसे विकसनशील देशों की बारी आई तो पीछे हटने लगे। यही बात दुनिया को भारी पड़ेगी। अमरीका के लिए भी यह अच्छी बात साबित नहीं होगी। वैसे भी रूस–यूक्रेन युद्ध से बहुत से देशों ने यह जाना कि डॉलर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खतरनाक होता जा रहा है और इसका विकल्प ढूँढना जरूरी है। चीन, यूरोप और भारत जैसे देशों ने अपने चलन को अंतरराष्ट्रीय चलन के रूप में प्रयोग में लाना शुरू किया है। बहुत सारे देश अपनी डॉलर पूंजी की जमा भी कम करने की कोशिश कर रहे है। यह बात सही है कि अब फिर से सोने पर आधारित व्यवस्था की ओर मुड़ना कठिन है लेकिन 'मल्टी करेन्सी' व्यवस्था पर ज़ोर दिया जा रहा है। यह अमरीका की नीति को नकारने का परिणाम कहा जा सकता है। अमरीका को चाहिए कि इसको समझे और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपनी मर्जी से प्रभावित करने की कोशिश ना करे। यही सभी के हित में होगा। ❑❑

संवेदनशीलता से प्रकृति के पुनर्जीवन की राह

पिछले पांच दशकों में वैश्विक आर्थिक प्रगति पांच गुना बढ़ी है, किंतु यहां तक पहुंचने के लिए 70 प्रतिशत से अधिक पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उनकी क्षमता से अधिक दोहन किया गया। इसका परिणाम यह कि पृथ्वी का अस्तित्व ही संकट में आ गया है।

बार–बार चेताने की आवश्यकता होती है कि इस ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सियां हैं, और हमारी गैलेक्सी में भी अरबों ग्रह हैं, किंतु उनमें केवल पृथ्वी ही ऐसी है, जहां जीवन संभव है। सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, जहां सतह पर जल उपलब्ध है और जो जीवन के अस्तित्व में सहायक है। निकट भविष्य में पृथ्वी के अलावा हमारी कोई और शरणस्थली नहीं बनने वाली।

संभवतः इसी कारण साल 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस के लिए, 5 जून 1974 के पहले पर्यावरण दिवस की थीम 'ओनली वन अर्थ –केवल एक ही पृथ्वी' को दोहराना जरूरी लगा। जहां 1974 में शायद ही यह कहा गया हो कि प्रकृति आपात स्थिति में है, वहीं 2022 तक ये चेतावनियां सर्वत्र सुनाई देने लगीं। मानवीय जरूरतों और लालच ने पृथ्वी को तीन मुख्य संकटों में जकड़ लिया है– जलवायु संकट, प्रकृति और जैव विविधता की हानि तथा प्रदूषण और अपशिष्ट का बढ़ता ढेर।

पिछले सौ वर्षों में आधे वेस्टलैंड और समुद्रों में आधे से अधिक मूंगे की चट्टानें नष्ट हो चुकी हैं। सागरों में इतना प्लास्टिक पहुंच रहा है कि 2050 तक वहां मछलियों से अधिक प्लास्टिक हो सकता है। पृथ्वी के प्रति संवेदना जगाने और इस बिगड़ते संतुलन को सुधारने के लिए ही 2021 के अर्थ डे की थीम थी– 'अपनी पृथ्वी को फिर से ठीक करें'। अप्रैल 2022 की थीम 'अपने ग्रह में निवेश करें', अर्थ डे 2020 की 'जलवायु पर सक्रियता' और 2019 की

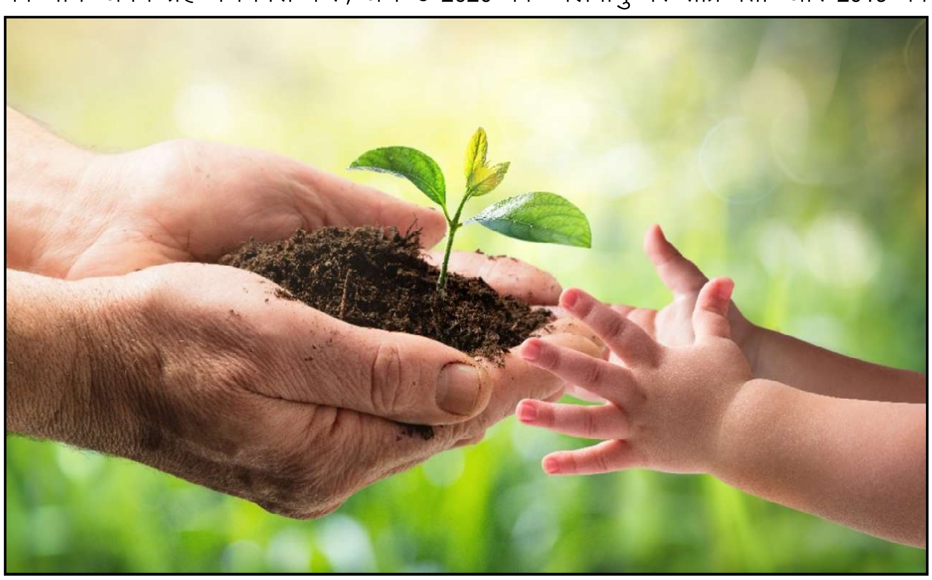

पृथ्वी तो हमारा साझा घर है। मानव को स्वयं से पूछना चाहिए कि उस पृथ्वी का क्या होगा जिसमें जैव विविधता ही नहीं बचेगी?

– **विजय गर्ग**

थीम थी 'अपनी प्रजातियों की रक्षा करें'।

साल 2021–2030 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र ने 'डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन' यानी पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया है। इसमें ताजा पानी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और भूमि आधारित इकोसिस्टम को फिर से पहले जैसी स्थिति में लाने के प्रयास जारी हैं। इसमें भूमि उपयोग परिवर्तन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी प्रयासों का निष्कर्ष था कि 5 जून, 2022 को एक बार फिर 'केवल एक पृथ्वी' के थीम पर लौटा जाए।

पृथ्वी और मानवता के लिए संकट का मुख्य कारण है– सतत उपभोग और सतत उत्पादन प्रणाली न होना। जनसंख्या वृद्धि के साथ यह समस्या बढ़ रही है। दूसरी ओर, जैव विविधता तेजी से घट रही है। अब तक 65 फीसदी वन्य जीव समाप्त हो चुके हैं। इसी कारण 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस पर यह भी आह्वान किया गया था कि हम सतत और पर्यावरण–अनुकूल जीवनशैली अपनाएं और पृथ्वी के साथ समरसता में जिएं। इस समरसता का भाव जगाने के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं को पृथ्वी के स्थान पर रखें और सोचें कि जो कुछ पृथ्वी और प्रकृति के साथ हो रहा है, यदि वही हमारे साथ हो रहा होता, तो हमें कैसा लगता?

संवेदनशील न्यायालय और न्यायिक संस्थाएं अब प्रकृति या उसके किसी हिस्से को वैधानिक रूप से जीवित मानव घोषित कर रही हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के आदेश भी दे रही हैं। हालांकि सरकारें ऐसे आदेशों को समय के साथ निरस्त कराने में सफल हो जाती हैं। कई बार, पर्यावरण और पृथ्वी के हित में उठी आवाज़ों को विकास विरोधी कहकर कमजोर करने का प्रयास करती हैं। यह भी निर्विवाद है कि पृथ्वी की हानि कम करने के प्रयास भी हो रहे हैं। मसलन, यूरोप में बांध हटाए जा रहे हैं। साल 2021 में यूरोप के 17 देशों में 239 बांध हटाए गए।

22 मई, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था–'हमने प्रकृति के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है, जबकि हमें तो उसका रक्षक होना चाहिए था।' प्रकृति हमें जीवन, अवसर, सेवाएं और समाधान देती है, किंतु हमने उसकी जैव विविधता को नष्ट किया और जलवायु संतुलन में बाधाएं डालीं। स्वस्थ पृथ्वी, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक है। अन्यथा, स्थिति यह है कि 90 प्रतिशत जनसंख्या प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है।

मानव के पृथ्वी पर पड़ते प्रभावों को लेकर चिंता पिछले पचास वर्षों से व्यक्त की जा रही है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र का पहला पर्यावरण सम्मेलन 'प्राकृतिक पर्यावरण' पर नहीं, बल्कि 'मानव पर्यावरण' पर केंद्रित था। इसी सम्मेलन में तय किया गया कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। दो वर्षों बाद 'केवल एक पृथ्वी है' के नारे के साथ पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था।

आज जरूरत है कि सरकारें, समाज और प्रत्येक व्यक्ति आत्ममंथन करें कि पृथ्वी के हित और अहित में उन्होंने क्या किया है। यदि हम प्रकृति को खुद ही पुनर्जीवित होने में मदद करें, तो वह भी पृथ्वी की सेवा ही होगी। कोरोना काल के प्रारंभिक दिनों में मानवीय गतिविधियां ठप्प होने के कारण नदियां, आकाश और वन्य जीवन स्वतः ही स्वच्छ–सजीव हो उठे थे। विशेष परियोजनाएं नहीं चलाई गई थीं, बस मानवीय हस्तक्षेप कम हो गया था। पशु–पक्षी, मछलियां और अन्य जीव–जंतु उन मार्गों पर लौट आए थे जो हमने उनसे छीन लिए थे।

पृथ्वी तो हमारा साझा घर है। मानव को स्वयं से पूछना चाहिए कि उस पृथ्वी का क्या होगा जिसमें जैव विविधता ही नहीं बचेगी? ❑❑

(विजय गर्ग– सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब)

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

देश में ऑनलाइन लूडो के बढ़ते खतरे पर कैसे लगेगी लगाम

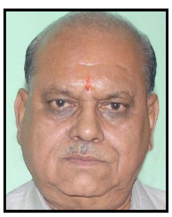

भारत में ऑनलाइन लूडो का चलन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर युवाओं और कम आय वर्ग के लोगों के बीच। इसकी आसान उपलब्धता और कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लालच ने लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है, बल्कि एक तरह का नशा बन गया है जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है।

–अजय कुमार

रमेश, एक मध्यमवर्गीय परिवार का साधारण युवक था। शहर के एक निजी कंपनी में मामूली वेतन पर काम करता और अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसकी दिनचर्या काम से घर और कभी–कभार दोस्तों के साथ चाय पीने तक ही सीमित थी। लेकिन कुछ महीने पहले, उसके एक सहकर्मी ने उसे ऑनलाइन लूडो के एक ऐप के बारे में बताया। शुरुआत में रमेश ने इसे सिर्फ मनोरंजन का एक साधन समझा। काम से लौटने के बाद या खाली समय में वह दोस्तों या अनजान लोगों के साथ लूडो खेलता, और कभी–कभार छोटी–मोटी बाजी भी लगा लेता।

शुरुआत में सब कुछ रोमांचक और मजेदार लग रहा था। जीत की खुशी और हार का मामूली गम, यह सब उसकी नीरस जिंदगी में एक नया रंग भर रहा था। धीरे–धीरे, रमेश इस खेल का आदी होता चला गया। अब वह काम के दौरान भी चोरी–छिपे लूडो खेलने लगा था, और घर पर परिवार को कम समय देता था। उसकी पत्नी अक्सर शिकायत करती कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा, हमेशा फोन में ही घुसा रहता है। रमेश इन बातों को अनसुना कर देता, उसे तो बस अगली बाजी जीतने की धुन सवार रहती थी।

एक दिन, रमेश ने एक बड़े दांव पर अपनी महीने भर की कमाई लगा दी। उसे पूरा भरोसा था कि वह जीत जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह बुरी तरह हार गया। इस हार ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह घर कैसे चलाएगा और अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। रातों की नींद उड़ गई, और वह हर समय उदास और चिड़चिड़ा रहने लगा। रमेश अकेला नहीं था जो इस ऑनलाइन लूडो के जाल में फंसा था। भारत में ऑनलाइन लूडो का चलन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर युवाओं और कम आय वर्ग के लोगों के बीच। इसकी आसान उपलब्धता और कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लालच ने लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है, बल्कि एक तरह का नशा बन गया है जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है।

ऑनलाइन लूडो के कई खतरे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला खतरा है आदत लगना और लत में बदलना। यह खेल इतना आकर्षक और आसान है कि लोग आसानी से इसके आदी हो जाते हैं। लगातार खेलने की इच्छा और हर बार जीतने की उम्मीद उन्हें घंटों तक स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देती है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। नींद की कमी, आंखों में दर्द, तनाव और चिंता जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। दूसरा बड़ा खतरा है वित्तीय नुकसान। ऑनलाइन लूडो में अक्सर पैसे की बाजी लगाई जाती है। जीतने का लालच लोगों को अपनी जमा पूंजी और यहां तक कि कर्ज लेकर भी दांव लगाने के लिए प्रेरित करता है। हारने पर उन्हें भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां लोगों ने कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या तक कर ली है। तीसरा खतरा है सामाजिक अलगाव। जो लोग ऑनलाइन लूडो के आदी हो जाते हैं,

वे धीरे–धीरे अपने परिवार और दोस्तों से दूर होने लगते हैं। उन्हें वास्तविक दुनिया से कोई सरोकार नहीं रह जाता और वे अपनी आभासी दुनिया में ही खोए रहते हैं। इससे उनके सामाजिक संबंध कमजोर हो जाते हैं और वे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। चौथा खतरा है धोखाधड़ी और जालसाजी। ऑनलाइन लूडो प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। कुछ ऐप गैरकानूनी तरीके से काम करते हैं और खिलाड़ियों से पैसे ऐंठ लेते हैं। इसके अलावा, कुछ खिलाड़ी हैकिंग या अन्य गलत तरीकों का इस्तेमाल करके दूसरों को हराते हैं, जिससे ईमानदार खिलाड़ियों को नुकसान होता है।

अब सवाल यह उठता है कि इस ऑनलाइन लूडो के बढ़ते खतरे पर लगाम कैसे लगाई जाए? इसके लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले लोगों को ऑनलाइन लूडो के खतरों के बारे में जागरूक करना होगा। इसके लिये सरकार और गैर–सरकारी संगठनों को मिलकर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताना चाहिए। मीडिया भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लोगों को यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि एक गंभीर लत बन सकता है जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।

इसके अलावा ऑनलाइन लूडो प्लेटफॉर्म को कानूनी दायरे में लाना जरूरी है। सरकार को ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए जो इन प्लेटफॉर्म की गतिविधियों को नियंत्रित करें और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करें। सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंसिंग और विनियमन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि धोखाधड़ी और जालसाजी को रोका जा सके। ऑनलाइन लूडो ऐप्स में ऐसे फीचर होने चाहिए जो खिलाड़ियों को अपनी खेलने की सीमा निर्धारित करने और समय–समय पर ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐप्स में एक चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए जो खिलाड़ियों को अत्यधिक खेलने या पैसे गंवाने पर सतर्क करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके लत लगने के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है और खिलाड़ियों को समय पर सहायता प्रदान की जा सकती है।

ऑनलाइन लूडो की लत के जो लोग शिकार हो चुके हैं, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना भी जरूरी है। सरकार को नशा मुक्ति केंद्रों और हेल्पलाइन नंबरों की स्थापना करनी चाहिए जहां ऐसे लोग मदद मांग सकें। परिवार और दोस्तों को भी ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें इस लत से बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए।इसके अलावा माता–पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे ऑनलाइन लूडो या किसी अन्य हानिकारक ऑनलाइन गेम के आदी न हों। बच्चों को स्क्रीन टाइम को सीमित करने और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

बहरहाल, विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन लूडो और अन्य ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने वाले स्टार प्रचारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की खबरें भी सामने आती रहती हैं। सितंबर 2024 में, तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी (टीएनओजीए) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने के लिए लगभग आधा दर्जन यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और एक निजी फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।टीएनओजीए ने इन सोशल मीडिया हस्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए और उनके जवाबों से असंतुष्ट होने पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सैदापेट में कानूनी कार्यवाही शुरू की। यदि दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है।खबरों के अनुसार, कुछ फिल्म हस्तियां जो पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने में शामिल थीं, वे भी जांच के दायरे में हैं।

कुल मिलाकर रमेश की कहानी एक चेतावनी है। उसने मनोरंजन के लिए खेलना शुरू किया था, लेकिन कब वह इस जाल में फंस गया उसे पता ही नहीं चला। वित्तीय नुकसान और पारिवारिक कलह के बाद, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक मनोचिकित्सक से सलाह ली और धीरे–धीरे इस लत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी कहानी उन लाखों लोगों के लिए एक सबक है जो ऑनलाइन लूडो के महाजाल को हल्के में ले रहे हैं।❑❑

(अजय कुमार– उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार है।)

भारतीय उत्पादों के लिए जरूरी है एक राष्ट्र–एक प्रतीक

जब भी खरीदारी करने हम किसी दुकान में जाते हैं तो सबसे पहली बात हमारे मस्तिष्क में कौन सी आती है? कीमत, डिजाइन, रंग, वारंटी। लेकिन क्या केवल इतनी जानकारी पर्याप्त हैं, शायद कुछ कमी है! सस्ते के चक्कर में कई बार हम अनजाने में ही ऐसे लोगों को बढ़ावा दे देते हैं जो प्रकारांतर से भारतीय उद्योगों को कमजोर करते रहे हैं। सामान खरीदते समय हम उसके देश का नाम जानने की कोशिश नहीं करते कि दरअसल यह उत्पाद कहां निर्मित हुआ है। इसका कारण यह नहीं है कि लोगों को इसका परवाह नहीं है अपितु इसलिए कि यह जानकारी या तो अक्सर उपलब्ध नहीं है अथवा ऐसी जगह दी गई है जो दिखाई नहीं देती या फिर पढ़ने योग्य नहीं होती।

कई उत्पादों पर मूल देश का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होता और वहीं कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिन पर तो यह लिखा ही नहीं होता। अगर लिखा भी होता है, तो वह अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में छोटे अक्षरों में किसी कोने अंतरे में छपा होता है जिसे खरीदार शायद ही पढ़ पाए या पढ़ता हो। भारत जैसे देश के उपभोक्ताओं के लिए तो यह एक टेढ़ी खीर जैसा है।

एक ऐसा देश जहाँ लाखों लोग अंग्रेजी नहीं जानते या अनपढ़ हैं, वहाँ टेक्स्ट–आधारित लेबल से खरीदारी के व्यवहार को प्रभावित करने की उम्मीद करना अवास्तविक है। यही कारण है कि हमें 'मेड इन इंडिया' के लिए 'एक राष्ट्र–एक प्रतीक' की आवश्यकता हैः एक विशिष्ट दृश्य चिह्न। जो प्रभाव एक लिखी हुई चीज आप पर डालती है उससे कहीं ज्यादा जल्दी और अच्छा प्रभाव एक चिन्ह आप पर डालता है। यह साक्षरता और भाषा से परे होता है क्योंकि खरीदार को पढ़ने की जगह सिर्फ इसे पहचानना होता है। जब वह प्रतीक साबुन की टिकिया, साड़ी, फोन चार्जर, रेडीमेड कपड़ों या खिलौने पर दिखाई देता है तो विकल्प स्पष्ट हो जाता हैः यह भारत का समर्थन करता है।

ऐसी दुनिया में जहाँ पहचान प्रभाव डालती है और प्रतीक शक्तिशाली याद रखते हैं,

हम सब मिलकर नागरिक, निर्माता, व्यवसाय और नीति निर्माता भारत को वह दें जिसका वह वास्तव में हकदार हैः एक प्रतीक। एक साझा गौरव। एक राष्ट्र। एक प्रतीक। मेड इन इंडिया के लिए।

–संगीता राव

मेरा मानना है कि भारत के लिए एक साहसिक और अचूक विचार के तहत एकजुट होने का समय आ गया है। भारत में बने सभी उत्पादों के लिए एक राष्ट्र, एक प्रतीक की दिशा में जल्दी से जल्दी प्रस्थान करना चाहिए।

इंडिया पॉजिटिव सिटिजन के संस्थापक के रूप में, जो राष्ट्र निर्माण के रोज़मर्रा के कार्यों को प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध एक आंदोलन है, मैंने जमीन पर काम करते हुए नागरिकों, उद्यमियों, कारीगरों और संस्थानों के साथ जुड़कर कई वर्ष बिताए हैं और इस यात्रा के माध्यम से, एक सच्चाई स्पष्ट हो गई हैः जब लाखों छोटे–छोटे कार्य एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो वे एक राष्ट्र की नियति को नया आकार देते हैं।

आज, भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। खादी से लेकर चिप्स, आयुर्वेद से लेकर ऑटोमोबाइल तक हम सब कुछ बनाते हैं। और इसमें से बहुत कुछ विश्व स्तरीय है। लेकिन हमारे पास जो कमी है वह है एक एकीकृत पहचान की। एक दृश्य प्रतीक की जो गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहता हैः यह मेड इन इंडिया है।

'मेड इन जापान' सटीकता को दर्शाता है। 'मेड इन जर्मनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का संकेत देता है। 'मेड इन इटली शैली और विलासिता की बात करता है। ये केवल लेबल नहीं हैं। ये दशकों में बने शक्तिशाली पहचान हैं–मजबूत प्रतीकों, मानकों और कहानियों द्वारा समर्थित। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश हर उत्पाद पर राष्ट्रीय लोगो का उपयोग करते हैं। खरीदार का विश्वास, गर्व और याददाश्त बढ़ाते हैं। यह निरंतरता उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाती है।

हमारे उद्यमी, कारीगर और इंजीनियर किसी से पीछे नहीं हैं। लेकिन अभी, एक हाथ से बुनी हुई साड़ी, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक हर्बल तेल और एक सॉफ्टवेयर नवाचार बाजार में आते हैं, लेकिन उन्हें भारतीय कहानी से जोड़ने वाला कोई सामान्य सूत्र नहीं है, अपितु यह एक खोया हुआ अवसर है और हमें इसे ठीक करना चाहिए।

बताते चले कि, 2020 में, कोविड लॉकडाउन के दौरान् मैंने एक विनियमन को उत्प्रेरित किया, जिसने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के लिए हर उत्पाद के लिए मूल देश को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया। इसने करोड़ों भारतीय उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खरीदारी करते समय सचेत, देशभक्तिपूर्ण खरीदारी विकल्प बनाने का अधिकार दिया।

उस अनुभव ने एक गहरी अंतर्दृष्टि को जन्म दिया है कि हम ऑफलाइन खुदरा बिक्री में समान स्पष्टता कैसे ला सकते है? हम मूल देश को कैसे दृश्यमान बना सकते हैं, तब भी जब पढ़ने के लिए कोई पाठ न हो?

तभी मेरे दिल में एक राष्ट्र, एक प्रतीक का विचार जड़ जमा गया। एक एकल, मजबूत चिन्ह जो भाषा, साक्षरता और भूगोल से परे है। एक प्रतीक जो गर्व से कहता हो कि उत्पाद भारतीय है। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं।

आखिर हमें ऐसे प्रतीक चिन्ह की जरूरत क्यों है? भारत केवल बहुभाषी नहीं है यह साक्षरता के स्तर और दृश्य प्रदर्शन में गहराई से विविधतापूर्ण है। हमारे पास 120 से अधिक प्रमुख भाषाएँ हैं। लाखों लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ नहीं सकते। वरिष्ठ नागरिक, ग्रामीण खरीदार और यहाँ तक कि दृष्टिबाधित नागरिक भी स्पष्टता और उत्पादन करने वाली एजेंसी के बारे में जानने के हकदार हैं।

'मेड इन इंडिया' लिखा हुआ लेबल हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया विजुअल प्रतीक अवश्य काम करेगा।

प्रतीक लोकतांत्रिक होता है। यह बिना शब्दों के बोलता है। यह हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाता है। यह भरोसे का शॉर्टकट बन जाता है। चाहे आप ओडिशा के आदिवासी गाँव में हो, बिहार के किराना स्टोर में हों या मुंबई के किसी महंगे स्टोर में। एक बार प्रतीक चिन्ह प्रचलन में आ जाए तो फिर वह हर बार सिर चढ़कर बोलता है।

आज हर भारतवासी विकसित भारत का सपना देख रहा है। भारत के विकास की असली कहानी भारतीय उत्पादों पर निर्भर करती है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की क्षमता लगातार बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत के नारे के तहत मेड इन इंडिया के उत्पादों की श्रृंखला लगातार बड़ी हो रही है। अब जरूरत है इन्हें अपनी पहचान के साथ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं के बीच ले जाने की। मेड इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह होर्डिंग्स, हाट बाजार, व्हाट्सएप विज्ञापनों और स्थानीय पैकेजिंग पर खूब फलेगा फूलेगा। यह लोगों की दृश्य स्मृति में जगह बना लेगा, जिससे भारत के लिए भारतीय निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देना और उनका समर्थन करना आसान हो जाएगा।

वास्तविक दुनिया में खरीदारी के क्षणों में रेलवे स्टेशन या नुक्कड़ की दुकान पर लोग जल्दी से चुनाव करते हैं। साबुन के पैकेट या मिठाई के डिब्बे पर एक जाना–पहचाना प्रतीक उन्हें तुरंत निर्णय लेने में मदद करता है। यह भारतीय उद्योगों का का समर्थन करता है। इसलिए इसे चुनने में लोगों को सहूलियत होगी।

एक प्रतीक चिन्ह हमारे उत्पादों को कई जीत दिला सकता है। एक आकर्षक, सुसंगत प्रतीक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को एक नजर में भारतीय उत्पादों की पहचान करने में मदद करेगा ठीक वैसे ही जैसे एप्पल का लोगो और स्विस क्रॉस।

(शेष पृष्ठ 35 पर ...)

अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट–वॉलमार्ट–भारत छोड़ो

हाल के दिनों में ई–कॉमर्स ने लोगों के जीवन को सुविधाजनक बना दिया है। जब हम इंटरनेट पर किसी वेब पोर्टल के माध्यम से किसी वस्तु (दृश्य) या सेवा की खरीद या बिक्री के लिए लेन–देन करते हैं, तो हम इसे ई–कॉमर्स कहते हैं। रेल या हवाई टिकट बुकिंग या होटल बुकिंग करना कुछ ही मिनटों का काम है। हम वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलकर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या किराने का सामान भी खरीद सकते हैं। भुगतान के विकल्प भी बहुत सुविधाजनक हैं। हम ऑनलाइन या नेट बैंकिंग या कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं।

सुविधा के कारण, ई–कॉमर्स इन दिनों फैशन में है। ई–कॉमर्स करने वाले 10,000 से ज़्यादा वेब पोर्टल हैं, लेकिन कुछ पोर्टल बहुत ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं। फ़्लिपकार्ट, मिंत्रा, होमशॉप 18, अमेज़न, ई–बे, ओला, उबर, मेक माई ट्रिप आदि कुछ ई–कॉमर्स पोर्टल हैं, जिनका कारोबार काफ़ी बढ़ गया है। इसके अलावा रेलवे बुकिंग वेब पोर्टल (आईआरसीटीसी) और एयरलाइंस के वेब पोर्टल भी अच्छा कारोबार कर रहे हैं। आज 70 प्रतिशत से अधिक रेलवे बुकिंग और लगभग 100 प्रतिशत एयरलाइन बुकिंग ऑनलाइन होती है।

पिछले कुछ समय में ई–कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। आज ई–कॉमर्स कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कुल खुदरा बाजार में ई–कॉमर्स खुदरा की हिस्सेदारी 2018 में 4 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 8 प्रतिशत हो गई है और 2028 तक 13–15 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। आज 82 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें 44.2 करोड़ इंटरनेट उपयोग करने वाले लोग तो ग्रामीण भारत से हैं। ऐसे में ई–कॉमर्स का भारत में विस्तार बढ़ता ही जा रहा है।

ई–कॉमर्स के फायदों के बावजूद, चिंता का मुख्य कारण यह है कि बड़ी ई–कॉमर्स कंपनियां अनैतिक तरीकों का उपयोग करके अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, और पारंपरिक दुकानदारों और छोटी ई–कॉमर्स फर्मों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर रही हैं। इन कंपनियों की रणनीति यह है कि वे भारी छूट देकर उपभोक्ताओं को लुभाती हैं, और घाटा उठाकर किसी तरह बाजार पर कब्जा कर लेती हैं। जहां पारंपरिक दुकानदार अधिकतम 10 से 20 प्रतिशत की छूट दे सकते हैं, वहीं बड़ी ई–कॉमर्स कंपनियां 30 से 50 प्रतिशत के बीच छूट देती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि ये अधिक छूट उनकी कार्यकुशलता के कारण नहीं, बल्कि बाजार पर कब्जा करने के उद्देश्य से घाटा उठाने की उनकी क्षमता के कारण है। ये कंपनियां अपनी उदारता के कारण छूट नहीं दे रही हैं, हालांकि, यह एक सोची–समझी रणनीति है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घाटा कई हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और आने वाले वर्षों में और भी बढ़ने वाला है। सबसे ज्यादा घाटा फिलपकार्ट, स्नैपडील जैसी बड़ी कंपनियों को हो रहा है। पिछले सालों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि ये कंपनियां लगातार घाटा उठाकर व्यवसाय कर रही हैं, और धीरे धीरे छोटे बड़े दुकानदारों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर रही हैं।

अनैतिक रणनीतिः कई बार ई कॉमर्स के समर्थक यह तर्क देते हैं कि ग्राहक ई–कॉमर्स के अनुभव से खुश हैं, क्योंकि उन्हें सस्ते दामों पर सामान मिल रहा है। कई बार यह भी तर्क दिया जाता है कि चूंकि इन कंपनियों की परिचालन लागत कम है, इसलिए ग्राहक ई–कॉमर्स के ज़रिए खरीदारी में अंततः लाभ कमाएंगे। हालांकि, हमें यह समझना चाहिए कि खरीद लागत से कम पर बेचने की रणनीति अनैतिक है और यह प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देती है; क्योंकि यह शिकारी (चतमकंजवतल) मूल्य निर्धारण का पालन करती है। पारंपरिक दुकानदारों, पुस्तक विक्रेताओं आदि को व्यवसाय से बाहर करके, वित्तीय ताकत का इस्तेमाल करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता है और इसलिए इसे रोकने की आवश्यकता है। ई–कॉमर्स कंपनियों द्वारा कर चोरी के संबंध में भी शिकायतें हैं।

क्या है समाधानः स्पष्ट रूप से, अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर कंपनियां न केवल पारंपरिक व्यवसाय को खत्म कर रही हैं, बल्कि ई–कॉमर्स में नए उद्यमियों के रास्ते में भी बड़ी बाधा बन रही हैं। चूंकि नए उद्यमियों के पास सीमित संसाधन हैं, इसलिए वे घाटे के मामले में विशाल ई–कॉमर्स कंपनियों का सामना नहीं कर सकते। विशाल संसाधनों वाली बड़ी कम्पनियों ने बाजार पर कब्जा करने के लिए शुरू में घाटा उठाने की रणनीति अपनाई है, और इसलिए यह 'स्टार्ट–अप' उद्यमों के लिए मौत की घंटी के समान है। यह खेद का विषय है कि अनुचित व्यवहारों से निपटने के लिए नियामक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) इन बड़ी ई–टेलर्स के अनैतिक व्यवहार को नियंत्रित करने में खुद को असहाय पा रहा है। जब पुस्तक विक्रेताओं ने इन कम्पनियों के खिलाफ शिकायत की कि ये कम्पनियां पुस्तकों पर भारी छूट देकर किताबें बेच रही हैं, यहां तक कि प्रकाशकों द्वारा इन कम्पनियों को दी जाने वाली छूट से भी ज़्यादा, तो भी सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाई। सीसीआई उनकी मांग पर विचार करने में असमर्थता जताता रहा है, क्योंकि उसका कहना था कि वह केवल ई–कॉमर्स व्यापारिक उपक्रमों से ही दोषी ई–कॉमर्स कम्पनियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें स्वीकार कर सकता है। बाद में सीसीआई ने भी उनके मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है।

क्या कानून इसकी इजाजत देता है?: बड़ा सवाल यह है कि क्या यह 'कैश बर्निंग बिजनेस मॉडल' जो प्रतिस्पर्धियों को खत्म कर देता है और स्थापित दुकानदारों और उद्यमियों को बाजार से दूर कर देता है, एक नैतिक बिजनेस मॉडल है। जवाब स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। वर्तमान समय में व्यापार में नैतिकता को रूढ़िवादी माना जा रहा है। हालाँकि, अगर हम इसे कानूनी दृष्टिकोण से भी देखें, तो यह बिजनेस मॉडल कानूनी रूप से भी मान्य नहीं है। 2016 से पहले देश के कानून के तहत ई–कॉमर्स में किसी भी प्रकार का विदेशी निवेश स्वीकार्य नहीं था। कानूनी मानदंडों का पालन नहीं करने वाली इन कंपनियों के संचालन को किसी तरह समायोजित करने के लिए 2016 में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) प्रेस नोट–3, 2016 के रूप में एक नीति ढांचा लेकर आया। हालांकि ई–कॉमर्स में एफडीआई की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसे तीन प्रमुख शर्तों के साथ मार्केटप्लेस मॉडल के लिए अनुमति दी गई थी। सबसे पहले, इन मार्केटप्लेस को वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित नहीं करना चाहिए और छूट नहीं देनी चाहिए। दूसरे, उन्हें इन्वेंटरी (स्टॉक) रखने की अनुमति नहीं थी और तीसरा, कोई भी विक्रेता 25 प्रतिशत से अधिक बिक्री नहीं करेगा। मई 2018 के महीने में, फ्लिपकार्ट ने वैश्विक खुदरा दिग्गज वॉलमार्ट के साथ अपनी 77 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री के लिए एक सौदा किया। फ्लिपकार्ट पर एफडीआई नियमों का उल्लंघन करने और कई तरीकों से कानून को दरकिनार करने के आरोप लग इन सबके लिए भारत के लिए एक स्पष्ट ई–कॉमर्स नीति की आवश्यकता है। नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था, लेकिन सभी सरकारी एजेंसियां, जिन्हें कानून का संरक्षक माना जाता है, चुपचाप इन कंपनियों को स्वतंत्र रूप से काम करने में मदद कर रही थीं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या एक कंपनी जो नकदी को जलाती रहती है और लगातार विदेशियों को शेयर बेचकर मुआवजा लेती है, यहां तक कि करों का भुगतान भी नहीं करती है जो विदेशी निवेश नियमों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), आरबीआई नियमों और कई अन्य सहित देश के कानून को दरकिनार करती है; क्या वह किसी अन्य बड़ी व्यावसायिक इकाई (वॉलमार्ट) को शेयर बेचकर बच निकल सकती है? क्या नियम केवल आम आदमी पर लागू होते हैं, बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं पर नहीं? इन कंपनियों को कंपनियों का मकड़जाल बनाने और नियामक निकायों को धोखा देने वाले शीर्ष वकीलों और सलाहकारों की मदद से कानूनों को दरकिनार करके काम करने की अनुमति क्यों दी गई, कानून के संरक्षक के रूप में सरकारी विभागों द्वारा उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

आज की दुनिया में ई–कॉमर्स ने अहमियत हासिल कर ली है। भारत में ई–कॉमर्स में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें कई छोटी कंपनियां तेजी से उभर रही हैं और कुछ दिग्गज कंपनियां विशाल भारतीय ई–कॉमर्स बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, उबर, ओला आदि कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कुछ को स्वदेशी कहा जाता है, इस अर्थ में कि उनके प्रमोटर भारतीय रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने विदेशी इक्विटी को आकर्षित किया और अंततः विदेशी निवेशकों का वर्चस्व हो गया। देश के कानून के अनुसार, ई–कॉमर्स में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। इसलिए, इन कंपनियों ने मार्केटप्लेस मॉडल के नाम पर विदेशी निवेश प्राप्त किया। इस तरह, पूर्ण रूप से ई–कॉमर्स व्यवसाय चलाते हुए, वे कानून को दरकिनार कर रहे हैं। 2018 में जारी ई–कॉमर्स नीति के मसौदे में कहा गया है, "बढ़ते ऑनलाइन खुदरा व्यापार की नींव में डेटा प्रवाह है। मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके मोबाइल फोन पर संचार न केवल भौतिक स्थान, वित्तीय विवरण और उपभोक्ता वरीयता सहित डेटा की एक विशाल सरणी उत्पन्न करता है, बल्कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की एक गतिशील प्रोफ़ाइल भी बनाता है ... उपभोक्ताओं द्वारा ब्राउज़िंग और खोज का इतिहास भी उपभोक्ता वरीयताओं की समृद्ध जानकारी उत्पन्न करता है ... खोज इतिहास को ट्रैक करके, ऑनलाइन खुदरा वेबसाइटें दर्जी–निर्मित विपणन सामग्री के साथ उपभोक्ताओं को लक्षित करने में सक्षम हैं।"

नकली सामानः हाल ही में, भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की दिल्ली शाखा ने प्रमुख ई–कॉमर्स वितरकों को निशाना बनाकर कई छापे मारे हैं और हजारों घटिया उत्पाद जब्त किए हैं। दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित अमेज़न सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदामों में टीम ने हजारों घटिया उत्पाद जब्त किए। 19 मार्च को की गई छापेमारी में गीजर, फूड मिक्सर और विभिन्न बिजली के उपकरणों सहित 3,500 से अधिक सामान जब्त किए गए हैं। टीम ने पाया कि बड़ी मात्रा में उत्पादों में या तो अनिवार्य आईएसआई मार्क का अभाव था या उन पर नकली आईएसआई लेबल थे। जब्त माल का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 70 लाख रुपये है। एक अलग छापे में, बीआईएस अधिकारियों ने दिल्ली के त्रिनगर में स्थित फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट

सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में स्पोर्ट्स फुटवियर का एक भंडार भी मिला, जो पैक करके भेजने के लिए तैयार था, जो आवश्यक आईएसआई मानकों को पूरा नहीं करता था और उसमें उचित निर्माण तिथि की जानकारी नहीं थी। इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 590 जोड़ी स्पोर्ट्स फुटवियर जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये है। इससे पहले भी तिरुवल्लूर जिले में ई–कॉमर्स दिग्गज अमेज़न और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापा मारा, जिसमें अनिवार्य प्रमाणीकरण के बिना बेचे जा रहे बड़ी मात्रा में उत्पाद जब्त किए। पुडुवॉयल में अमेज़न के गोदाम में, अधिकारियों ने इंसुलेटेड फ्लास्क, खाद्य कंटेनर, धातु की पीने योग्य पानी की बोतलें, छत के पंखे और बीआईएस मानक चिह्नों के बिना खिलौनों सहित 3,376 वस्तुओं को जब्त किया। जब्त उत्पादों की कीमत 36 लाख रुपये है। यह संदेह से परे साबित हो गया है कि ये ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म नियम–मानक और नकली उत्पाद बेचकर उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं।

लेकिन ई–कॉमर्स दिग्गजों से नियमों का पालन कैसे करवाया जाए? वर्तमान में, नियम ई–कॉमर्स मार्केटप्लेस पर प्रतिबंध लगाते हैं, ताकि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की कीमत को प्रभावित न करें। ई–कॉमर्स मार्केटप्लेस की समूह कंपनियों पर इस प्रतिबंध को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे वर्तमान नियमों की खामियों को दूर किया जा सकेगा। भारत को एक अच्छी तरह से परिभाषित ई–कॉमर्स नीति की तत्काल आवश्यकता है, न केवल समान अवसर प्रदान करने के लिए, बल्कि विश्व व्यापार संगठन और अन्य क्षेत्रीय व्यापार वार्ताओं में बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए भी। स्वदेशी जागरण मंच का दृढ़ विश्वास है कि बहुराष्ट्रीय विदेशी ई–कॉमर्स कंपनियाँ भारत में अवैध व्यापार प्रथाओं में लिप्त हैं। ये फ़र्म अप्पारियो रिटेल जैसी मुखौटा कंपनियों के माध्यम से नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं, जो कि शिकारी मूल्य निर्धारण और छूट में लिप्त हैं, जिससे ऑफ़लाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे विक्रेताओं का व्यवसाय नष्ट हो रहा है। विदेशी ई–कॉमर्स कंपनियों से ऑफ़लाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन लाया जाना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच को उम्मीद है कि 'अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट–वॉलमार्ट का बहिष्कार' 'भारत छोड़ो' अभियान उपभोक्ताओं और सरकार को एफडीआई ई–कॉमर्स कंपनियों के उत्पादों को पूरी तरह से अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा और भारतीय विक्रेताओं के चेहरों पर मुस्कान वापस लाएगा। केंद्र को उपभोक्ताओं के साथ–साथ ऑफलाइन व्यापारियों और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए एक "सर्वव्यापी" नीति लानी चाहिए। ❑❑

(पृष्ठ 32 से जारी ...)

भारतीय उत्पादों के लिए जरूरी है एक राष्ट्र–एक प्रतीक...

जब भारतीय प्रतीक देखेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि उनकी खरीदारी घरेलू उद्योगों के नवाचार, नौकरियों और स्थिरता का समर्थन करती है।

छोटे व्यवसायों के पास अक्सर बड़े बजट की कमी होती है। यह प्रतीक उनका मूक राजदूत बन जाता है बिना किसी लागत के विश्वसनीयता बढ़ाता है।

गुणवत्ता के लिए प्रोत्साहन में भी ऐसा सहायक होगा। प्रतीक का उपयोग गुणवत्ता मानकों से जोड़ा जा सकता है। निर्माताओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।

'साझा पहचान बनाएं' छात्रों से लेकर गृहणियों तक, हर भारतीय एक ही चिह्न वाले उत्पादों को देखकर और उनका उपयोग करके एक बड़ी राष्ट्रीय यात्रा का हिस्सा महसूस करेगा।

इस विचार को सफल बनाने के लिए, हमें एक सोच–समझकर तैयार किए गए प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता है जो भारतीय विरासत में निहित हो, लेकिन आधुनिक और वैश्विक हो।

डिजाइन उत्कृष्टता, स्पष्ट पात्रता और मानक, सार्वजनिक–निजी सहयोग, एक शक्तिशाली राष्ट्रीय संचार अभियान के जरिए हमें प्रतीक चिन्ह को समर्थन देना चाहिए। देश की आम राय से ते हुए प्रतीक चिन्ह को जिम्मेवारी के साथ स्कूली किताबें और कक्षाएँ, खुदरा पैकेजिंग और निर्यात सामग्री,सरकारी पोर्टल और दूतावास शोकेस, ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म और हाट,सिनेमा, प्रभावशाली व्यक्ति, पॉप संस्कृति और विज्ञापन हर जगह प्रमुखता से शामिल करना होगा। इसेनाम मात्र के मोहर की जगह विशुद्ध भारतीय आत्मा से जोड़ना होगा।

कहानी सुनाने में तो यह एक सरल विचार है लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारतीय व्यापार के लिए यह एक बड़ी छलांग कजरिया बन सकता है।

क्योंकि एक राष्ट्र, एक प्रतीक का विचार किसी भी ब्रांडिंग से कहीं बढ़कर है। यह पहचान, विश्वास और राष्ट्रीय एकता के बारे में है। यह दुनिया को और खुद को यह बताने के बारे में है कि हम निर्माताओं, रचनाकारों और योगदानकर्ताओं का देश हैं। कई भाषाओं वाले देश में, एक दृश्य प्रतीक हमारी साझा आवाज बन जाता है। मेरा मानना है कि यह अगली बड़ी छलांग है जो भारत को आजमाना चाहिए। मैं इसे साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आईए हम सब मिलकर नागरिक, निर्माता, व्यवसाय और नीति निर्माता भारत को वह दें जिसका वह वास्तव में हकदार हैः एक प्रतीक। एक साझा गौरव। एक राष्ट्र। एक प्रतीक। मेड इन इंडिया के लिए। ❑❑

सविता रावः *संस्थापक, इंडिया पॉजिटिव सिटिजन।*
www.indiapositivecitizen.com

ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ व्यापारियों का रोष मार्च

चंवरा चौफुल्या में व्यापारियों ने ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ रोष मार्च निकाला। स्वदेशी जागरण मंच, झुंझुनूं के बैनर तले सेवानिवृत्त सीबीईओ हमीर सिंह और रुड़सिंह शेखावत के नेतृत्व में दर्जनों दुकानदार शामिल हुए।

मंच के पूर्णकालिक कार्यकर्ता ब्रह्मदत्त मीणा ने कहा कि विदेशी कंपनियां भारी छूट और लुभावने विज्ञापनों से ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। इससे स्थानीय बाजार की रीढ़ टूट रही है। हमीर सिंह और रुड़सिंह शेखावत ने कहा कि इन कंपनियों के कारण छोटे दुकानदारों की आय में भारी गिरावट आई है। कई व्यापारियों के लिए दुकान का किराया, बिजली बिल और कर्मचारियों का वेतन निकालना भी मुश्किल हो गया है। सरकार से मांग की गई कि इन पर तुरंत लगाम लगाया जाए। कपड़ा व्यापारी विक्रम गुर्जर ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में आमदनी आधी रह गई है। स्थानीय दुकानदार ग्राहकों को उधार और मानवीय सुविधा देते हैं। ऑनलाइन कंपनियां उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी कर रही हैं। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से अपील की कि ऑनलाइन कंपनियों पर सख्त नीति बनाई जाए। स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। पुरुषोत्तम सोनी, देशराज सैनी, अशलम चौधरी, नरेन्द्र सैनी, रामस्वरूप सैनी, जितेन्द्र सैनी, अन्तेस मीणा, जेपी सैनी, डीपी खल्वा, चतर सिंह, बाबूलाल, महिपाल खल्वा खोहसहित कई दुकानदार मौजूद रहे।

स्वदेशी, स्वावलंबन, उद्यमिता यानि आत्मनिर्भर भारतः सतीश कुमार

स्वदेशी स्वावलंबन और उद्यमिता के साथ ही युवा इस देश को महान बना सकते हैं। भारत युवाओं का देश है, ऐसे में भारत को विश्व की महान आर्थिक शक्ति बनाने में युवा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यह बात स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंगठक श्री सतीश कुमार ने आदर्श नगर स्थित चोयल वॉलमार्ट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, स्वदेशी जागरण मंच भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं में स्वदेशी स्वावलंबन, उद्यमिता के साथ स्वरोजगार विषय पर काम कर रहा है, जिसमें युवा अपनी पढ़ाई के साथ तकनीकी कार्यों का कौशल सीखकर अपने लघु और कुटीर उद्योग जिंदा रह सके। उन्होंने बताया कि मेरा स्वावलंबी भारत अभियान के तहत युवा डिजिटल माध्यम से जुड़कर स्वालंबन और उद्यमिता के साथ अपना स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस डिजिटल माध्यम से युवा को स्वालंबन हेतु संपूर्ण जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी।

जानेमाने उद्योगपति राधेश्याम चोयल ने स्वालंबी भारत अभियान के डिजिटल प्लेटफॉर्म की संपूर्ण जानकारी से बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी स्वालंबन अभियान के तहत ही स्वावलंबी भारत अभियान का डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक युवा तक पहुंचे। युवा इस प्लेटफार्म के साथ जुड़कर अपनी रोजगार संबंधी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। देश भर में 750 रोजगार सृजन केंद्र का निर्माण प्रत्येक जिला स्तर पर करने की योजना है। संपूर्ण देश में 400 रोजगार सृजन केदो की स्थापना की गई है। जल्द ही देश के अन्य सभी जिला केंद्रों पर रोजगार सृजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

इस अवसर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के प्राचार्य डॉ मनोज अग्रवाल, डॉक्टर अरुण अरोड़ा, ग्राहक पंचायत से राधेश्याम अग्रवाल, चित्तौड़ प्रांत संयोजक डॉ संत कुमार, अजमेर विभाग संयोजक दिलीप कुमार चौहान, विभाग सहसंयोजक डॉ कुलदीप सिंह शेखावत, महानगर सहसंयोजक राहुल शर्मा, महिला प्रमुख डॉक्टर सुचित्रा राठौर, गरिमा गोयल, पूनम शर्मा, मोनिका अरोड़ा, शैतान लाल, ललित कुमार दांगी, डॉ महावीर प्रसाद, सज्जन सिंह सहित भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, भारत विकास परिषद, विश्व हिंदू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

विदेशी कंपनियों के माल का हो पूर्ण बहिष्कारः डॉ. महाजन

हमारे उपभोक्ताओं को सस्ते माल का लालच देकर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है। हमारे देश को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए हमें हमारी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। हमारे उपभोक्ता हमारी अर्थव्यवस्था के सिपाही है। अतः सभी देशवासियों को अर्थव्यवस्था के सिपाही के रूप में विदेशी कंपनियों द्वारा ई–कॉमर्स या किसी और तरीके से बेची जा रही सवाएं या माल का पूर्ण बहिष्कार करना

समय की आवश्यकता है। ऐसी अपील स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने की।

वे नागपुर में टीम कैट नागपुर द्वारा आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। डॉ. महाजन ने इस मौके पर शहर के व्यापारियों के साथ वार्ता की और स्वदेशी संबंधित बैठक ली। उन्होंने कहा कि देशभर में कैट के सहयोग से व्यापारी संगठनों को जोड़कर विदेशी कंपनियों के खिलाफ राष्ट्र–व्यापी अभियान चलाएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजॉन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला जैसी कंपनियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह कंपनियां हमारे देश के नियमों का उल्लंघन कर रही है। सरकार के अनेक विभाग जैसे ईडी, सीबीआई, कंपटीशन कमिशन आदि इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देशवासी इन से माल खरीद कर अभी भी इनके साथ है। देशवासियों को स्वदेशी माल और सेवाएं बेचने वाले बाजारों के दुकानों से माल खरीदना पड़ेगा तभी जाकर देश शक्तिशाली बनेगा।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि पहलगाम के दुर्दैवी घटनाक्रम की भीषणता को देखते हुये बदलते हालात में व्यापारी समुदाय को सरकार के साथ देशहित में खड़ा रहना चाहिए। भरतिया ने कहा कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां कानून का उल्लंघन करके अपने पैसों का नुकसान करते हुए देश के व्यापारी और व्यापार को चौपट कर रही है। ऐसी कंपनियों के विरोध में देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। आने वाली 16 मई को दिल्ली में कैट और स्वदेशी जागरण मंच की बैठक में देश भर के व्यापारियों के साथ मिलकर इन कंपनियों के विरोध में अभियान की रूपरेखा तय की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन सचिव विनोद गुप्ता ने किया।

कार्यक्रम में विशेष रूप से कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया, चेयरमैन गोपाल अग्रवाल, अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, संरक्षक किशोर धाराशिवकर, सचिव विनोद गुप्ता, धनंजय भिड़े, रविंद्र गुप्ता, गोविंद पटेल, सुषमा त्रिपाठी, जैश वर्मा, जयश्री गुप्ता, डॉक्टर चौधरी डॉक्टर प्रेमलता तिवारी, कल्पना पांडे, संतोष गुप्ता, विजय चौरसिया, राजू हरडे, सारंग ढावले, मनुभाई सोनी, मधुसूदन सारडा, किशोर राठौड़, हर्ष गुप्ता, आनंद अग्रवाल, आरती गुप्ता, आशा माथुर, रूपा नंदी, दीपा पचौरी, आरती बदल, दीपाली, गजानन रोहतक आदि उपस्थित थे।

ऑनलाइन शापिंग से निजी डाटा के खतरेः कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि ऑनलाइन शापिंग से हमारी व्यक्तिगत जानकारियां विदेशी कम्पनियों के पास पहुंच रही हैं, जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा इससे स्थानीय रोजगार के अवसर छिन रहे हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच की ओर से जन जागरण अभियान शुरू करके लोगों को स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लाल ने कहा कि आजकल अमेरिकी कम्पनियों जैसे अमेजान और फ्लिपकार्ट का ट्रेड बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। बाजार में लगभग 68 फीसदी हिस्सेदारी इनकी हो चुकी है। इन कम्पनियों द्वारा अक्सर लोगों को गुणवत्ताहीन घटिया या नकली सामान दिया जा रहा है। इसके अलावा यह कम्पनियां स्थानीय रोजगार को भी छीन रही हैं। इनकी ट्रेडिंग की वजह से स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनलाइन शापिंग के जरिये महत्वपूर्ण जानकारियां इन कम्पनियों तक पहुंच रही हैं, जो भविष्य के लिए घातक हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच व्यापार संगठनों के साथ मिलकर इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है कि लोग स्थानीय दुकानदारों से भी ऑनलाइन खरीदारी कर सकें। इसमें आन जनमानस का सहयोग बहुत आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

स्वदेशी जागरण मंच और कैट ने तुर्किये और अजरबैजान के साथ व्यापार के बहिष्कार का किया एलान

स्वदेशी जागरण मंच और व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने तुर्किये और अजरबैजान के साथ सभी कारोबारी और पर्यटन सम्बन्धों को खत्म करने का एलान किया। कैट द्वारा राजधानी नयी दिल्ली के होटल ललित में आयोजित राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में देशभर से आये 125 से अधिक शीर्ष व्यापारिक नेताओं ने सर्वसम्मति से दोनों देशों के साथ सभी कारोबारी और पर्यटन सम्बन्धों को खत्म करने का संकल्प लिया।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि देश के 24 राज्यों से आये 125 से अधिक व्यापारी प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में तुर्किये और अजरबैजान के साथ सभी कारोबारी और पर्यटन सम्बन्धों को खत्म करने का निर्णय लिया है। इस सम्मेलन में पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन और कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया सहित अन्य कारोबारी नेता मौजूद रहे।

खंडेलवाल ने बताया कि राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में देशभर से आये हुए 125 से ज्यादा शीर्ष व्यापारिक नेताओं ने सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया है कि भारत का व्यापारिक समुदाय तुर्किये और अजरबैजान के साथ हर प्रकार के व्यापार एवं व्यावसायिक सम्बन्धों का पूर्ण बहिष्कार करेगा, जिसमें यात्रा और पर्यटन भी शामिल है। व्यापारिक समुदाय ने भारतीय फिल्म उद्योग से भी अपील की है कि वे तुर्किये और अजरबैजान में किसी भी प्रकार की फिल्म की शूटिंग न करें। यदि कोई फिल्म वहां शूट होती है, तो व्यापार जगत और आम जनता ऐसे फिल्मों का बहिष्कार करेगी। सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी कॉरपोरेट हाउस तुर्की और अजरबैजान में अपने उत्पादों के प्रमोशन की शूटिंग नहीं करेगा।

https://samacharsamrat.com/cait-announced-boycott-of-trade-with-turkey-and-azerbaijan/

भारत के लिए एक स्पष्ट ई–कॉमर्स नीति की जरुरत : बरियार

हाल के दिनों में ई–कॉमर्स ने लोगों के जीवन को सुविधाजनक बना दिया है। जब हम इंटरनेट पर किसी वेब पोर्टल के माध्यम से किसी वस्तु (दृश्य) या सेवा की खरीद या बिक्री के लिए लेन–देन करते हैं, तो हम इसे ई–कॉमर्स कहते हैं। रेल या हवाई टिकट बुकिंग या होटल बुकिंग करना कुछ ही मिनटों का काम है। हम वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलकर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या किराने का सामान भी खरीद सकते हैं। भुगतान के विकल्प भी बहुत सुविधाजनक हैं। हम ऑनलाइन या नेट बैंकिंग या कैश ऑन डिलीवरी के जरिए भुगतान कर सकते हैं। सुविधा के कारण, ई–कॉमर्स इन दिनों फैशन में है। ई–कॉमर्स करने वाले 10,000 से ज्यादा वेब पोर्टल हैं, लेकिन कुछ पोर्टल बहुत ज्यादा कारोबार कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, होमशॉप 18, अमेजन, ई–बे, ओला, उबर, मेक माई ट्रिप आदि कुछ ई–कॉमर्स पोर्टल हैं, जिनका कारोबार काफी बढ़ गया है। इसके अलावा रेलवे बुकिंग वेब पोर्टल (आईआरसीटीसी) और एयरलाइंस के वेब पोर्टल भी अच्छा कारोबार कर रहे हैं। आज 70 प्रतिशत से अधिक रेलवे बुकिंग और लगभग 100 प्रतिशत एयरलाइन बुकिंग ऑनलाइन होती है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय मेला प्रमुख सचिंद्र कुमार बरियार कहा कि मंच ने अनुमान लगाया है कि पिछले कुछ समय में ई–कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। आज ई–कॉमर्स कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कुल खुदरा बाजार में ई–कॉमर्स खुदरा की हिस्सेदारी 2018 में 4 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 8 प्रतिशत हो गई है और 2028 तक 13–15 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। आज 82 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें 44.2 करोड़ इंटरनेट उपयोग करने वाले लोग तो ग्रामीण भारत से हैं। ऐसे में ई–कॉमर्स का भारत में विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। श्री बरियार ने कहा कि ई–कॉमर्स के फायदों के बावजूद, चिंता का मुख्य कारण यह है कि बड़ी ई–कॉमर्स कंपनियां अनैतिक तरीकों का उपयोग करके अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और पारंपरिक दुकानदारों और छोटी ई–कॉमर्स फर्मों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर रही हैं। इन कंपनियों की रणनीति यह है कि वे भारी छूट देकर उपभोक्ताओं को लुभाती हैं, और घाटा उठाकर किसी तरह बाजार पर कब्जा कर लेती हैं। श्री बरियार ने कहा कि इससे बचने के लिए भारत को एक स्पष्ट ई–कॉमर्स नीति की जरूरत है। केन्द्र सरकार को इस पर जल्द विचार करना चाहिए। ❑❑

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी कार्यक्रम

सचित्र झलक

गोवाहाटी विचार वर्ग

लखनऊ (प्रवास)

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

हरदोई (प्रवास)

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 मई 2025
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट–वॉलमार्ट के खिलाफ प्रदर्शन

सचित्र झलक

फिरोजपुर, पंजाब

गांधी नगर, गुजरात

झुंझुनू, जयपुर

अमृतसर, पंजाब

संगरूर, पंजाब

भोपाल, मध्य प्रदेश

फाजिल्का, पंजाब

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती